राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 44 ■ अंक 03 ■ जुलाई 2022 ■ ₹ 10 ■ पृष्ठ 36

सुरक्षित हैं सीमाएं

परिषद गतिविधियां

अभाविप तेलंगाना प्रांत कार्यालय लोकापर्ण के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते पूज्य सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी, मंचासीन अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान जी, राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी व अन्य

अभाविप जम्मू - कश्मीर प्रांत द्वारा पूंछ में आयोजित मिशन साहसी कार्यक्रम में प्रदर्शन करती छात्राएं

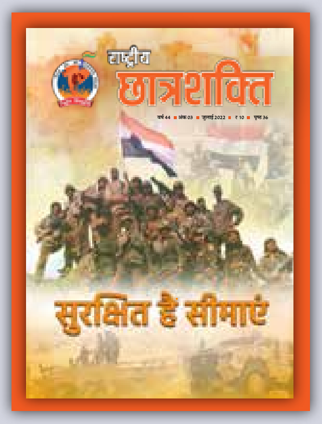

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 44, अंक 03
जुलाई, 2022

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रीत।

इस अंक में

05

कारगिल विजय
पराक्रम एवं शौर्य की अमिट गाथा

कारगिल युद्ध भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की अमिट गाथा है। 23 वर्ष पूर्व 26 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस एवं पराक्रम से पाकिस्तानी सेना को घूटनो के बल ला दिया था। कारगिल का यह युद्ध कई मायनों में अलग था, क्योंकि हमारे सैनिकों ...

संपादकीय	04
PARAMVIRS OF KARGIL WAR	07
लद्दाख में स्वदेश निर्मित इन्फ्रेंट्री प्रोटेक्टिड मोबिलिटी व्हीकल्स की तैनाती, दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने में होगी आसानी	09
NEW STRATEGIC ALIGNMENTS PRESUPPOSE NEW TRADE ROUTES	11
राजस्थान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का हंगामा, नवनिर्मित पुस्तकालय को खोलने की मांग	13
कानून के शिकंजे में कांग्रेस नेतृत्व : संजीव कुमार सिन्हा	14
राष्ट्रीय कला मंच द्वारा सिरोही में 'इंद्रधनुष' कार्यक्रम का आयोजन	16
धर्मान्तरित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने के लिए मुखर हुआ समाज : शरद चव्हाण	17
सृजनशीलता के साथ राष्ट्र प्रथम का भाव सिखाती है अभाविप : साक्षी सिंह	19
CALL FOR SWARAJ IN THE KHASI HILLS : ANANDITA SINGH	20
कानपुर : एचबीटीयू में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में अभाविप का प्रदर्शन	22
फिरोजाबाद : अवैध वसूली करने वाले विद्यालय प्रशासन के खिलाफ अभाविप ने की कार्रवाई की मांग	23
अभाविप कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के ऑडनकॉल पास का किया फतह, समुद्रतल से 5490 मीटर ऊंचे खतलिंग ग्लेशियर के समीप लहराया अभाविप का झंडा : सोनी मिश्र	24
हूल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर अभाविप ने किया अमर बलिदानी सिदो–कान्हू के कृतित्व को याद	25
ABVP TELANGANA STATE OFFICE INAUGURATED BY MANANIYA MOHAN JI	26
असली भारत तो गांवों में बसता है : नीखरा	28
मंडी : अभाविप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 'अभ्युदय' का आयोजन	29
ABVP, DUSU MEET V–C, CALL FOR CENTRE TO GUIDE STUDENTS	29
उदयपुर में जेहाद प्रणीत क्रूर हत्या के दोषियों पर हो शीघ्र कार्रवाई: अभाविप	30
तीनों सेनाओं के नेतृत्व द्वारा स्वीकार्य अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना सामरिक दृष्टि से आवश्यक: अभाविप	30
यूपीए की एजेन्ट तीस्ता के षडयंत्र के अंत की कहानी	31

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

जुलाई माह करगिल के संघर्ष की स्मृति लेकर आता है। बड़ी संख्या में अपने वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान देकर यह विजय अर्जित की थी।

भारत को हजार घाव देने की पाकिस्तान की नीति का ही विस्तार करगिल का युद्ध था। हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों पर लड़ा गया यह युद्ध न केवल सैनिकों के शौर्य का प्रकटीकरण था बल्कि पूरे देश में जिस प्रकार की राष्ट्रीय भावनाएं जाग्रत हुई थीं वह अभूतपूर्व थी। राजनैतिक मतभेदों को दूर कर पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ था।

करगिल के उस भावनात्मक दौर के बाद देश ने शासकीय दृष्टि से दो कालखण्डों का साक्षात्कार किया है। 2004 से 2014 के बीच आर्थिक, नैतिक और लोकतांत्रिक पतन का दुर्भाग्यशाली कालखण्ड आया जब राजनैतिक मतभेदों ने रंजिश का रूप धारण किया। इसी समय हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले सामने आये, सार्वजनिक सम्पत्ति की खुली लूट हुई और राष्ट्रीय मुख्यधारा को अपमानित करने के लिये भगवा आतंकवाद जैसे जुमले गढ़े गये।

2014 के बाद स्थिति में बदलाव आया। सत्ता परिवर्तन हुआ। भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम लगी। किन्तु जिन नीतियों के चलते जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया उन पर पुनर्विचार करने के बजाय पिछले कार्यकाल में जो राजनैतिक कटुता उत्पन्न हुई उसे बढ़ाने का ही काम किया गया। जनता के निर्णय पर ही प्रश्नचिन्ह लगाया गया।

करगिल के संदर्भ में पिछले दशकों की चर्चा इसलिये क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार की गतिविधियाँ देश में जारी हैं वह देश को साम्प्रदायिक विभाजन की ओर ले जाती दिख रही हैं। नूपुर शर्मा के बहाने देश में तनाव पैदा करने की कोशिश और गला काटने की घटनाओं पर विपक्ष की चुप्पी अच्छे संकेत नहीं देती। भले ही इन घटनाओं पर चुप्पी साधने वाले लोग केवल अपने राजनैतिक हिताहित के आधार पर यह स्टैं ले रहे हों किन्तु उन्हें अपनी नीति निर्धारित करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि वे अनजाने में देश के सद्भावपूर्ण वातावरण को चोट पहुंचाने का पाप तो नहीं कर रहे।

इन चिंताजनक परिस्थितियों मे एक आशा किरण के रूप में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है जिसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में समारोहपूर्वक मनाने से देशभक्ति का माहौल बनाया जा सकता है। शताब्दियों से हर मतभेद, हर खाई को पाटने और सभी देशवासियों को एकजुट करने में राष्ट्रीयता का भाव केन्द्रीय बिन्दु रहा है। वन्दे मातरम इसका सिद्ध मंत्र है। अभाविप ने इस 15 अगस्त को देश के दो लाख गाँवों में जाकर तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य लिया है वह समाज को विभाजित करने वाली सभी गतिविधियों का रचनात्मक प्रत्युत्तर है।

हार्दिक शुभकामना सहित,
आपका संपादक

कारगिल विजय
पराक्रम एवं शौर्य की अमित गाथा

| अजीत कुमार सिंह |

कारगिल युद्ध भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की अमिट गाथा है। 23 वर्ष पूर्व 26 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस एवं पराक्रम से पाकिस्तानी सेना को घूटनों के बल ला दिया था। कारगिल का यह युद्ध कई मायनों में अलग था, क्योंकि हमारे सैनिकों ने जिन विषम परिस्थितियों में दुश्मनों का मुकाबला किया वो अवर्णनीय है। दुर्गम पहाड़ों में बिना भोजन-पानी के सप्ताह - सप्ताह भर डटे रहना, समान्य सी बात नहीं थी। हमारे जवानों पर एक तरफ दुश्मन गोले बरसा रहे थे तो दूसरी तरफ प्रकृति भी...उनके धैर्य की परीक्षा लेने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। चोटी पर दुश्मन और सैनिकों के सामने पर्वत की खड़ी चुनौती। चहुंओर बर्फ ही बर्फ। खाने-पीने की सामग्री का अकाल...इन सब पर हमारी सेना ने हार नहीं मानी और असंभव को संभव कर दुनिया को चकित कर दिया। इस युद्ध को भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय' चलाकर जीता था। पीठ पीछे पाकिस्तान की ओर से वार किए जाने के बाद भी भारतीय जवानों का साहस हिमालय से भी ऊंचा था। भारतीय सेना के अदम्य शौर्य ने बड़ी विजय दिलाई थी। कारगिल की ऊंची चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवाते हुए वीरगति प्राप्त होने वाले देश के अमर बलिदानियों की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है

लेह लद्दाख की भारतीय सीमा को राज्य के उत्तरी इलाकों से अलग करने के उद्देश्य की गई इस घुसपैठ ने भारतीय सेना को चौंका दिया था। यह घुसपैठ उस समय हुई जब भारत – पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी को कम करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने फरवरी, 1999 में लाहौर घोषणापत्र में हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने कश्मीर मुद्दों पर आपसी बातचीत से सुलझाने की सहमति बनाई लेकिन पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों को नहीं छोंडा और अपने सैनिकों को चोरी-छिपे नियंत्रण रेखा पार कर भारत भेजना शुरू कर दिया। इसे पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन बंद्र' नाम दिया। इसके पीछे उसकी मंशा राष्ट्रीय राजमार्ग - 1 की आपूर्ति (सप्लाई) को बंद करवाना था, चूंकि यह राजमार्ग/हाईवे श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। उन्हें लगता था कि ऐसा करने पर कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़कर भारतीय सेना को वे सियाचीन ग्लेशियर से हटाने में सफल हो जाएंगे साथ ही आपूर्ति(सप्लाई) बंद होने से भारतीय सेना त्वरित जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि कारगिल हमले का वृहद् पक्ष, एक दूसरा पहलू भी था, जो कि राज्य के सबसे छोटे हिस्से कश्मीर

से जुड़ा हुआ था जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया क्योंकि कारगिल हमले के बाद भारतीय सेना इतना मुहतोड़ जवाब देगी इसकी कल्पना पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को नहीं थी। इस वृहद् पक्ष के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान प्रमुख मुल्ला महसूद रब्बानी से कश्मीर में जेहाद लड़ने के लिए पाकिस्तान ने 20 से 30 हजार लड़ाको की मांग की थी। रब्बानी ने 50 हजार लड़ाकों का वायदा कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी इस प्रस्ताव से बेहद खुश थे। बताया जाता है कि कारगिल को लेकर परवेज़ मुशर्रफ़ बेचैन था। 1965 के युद्ध से पहले कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना थी, सुरक्षा और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर थी, लेकिन 1965 और 1971 के युद्ध में भारत ने यह महत्वपूर्ण चोटियां अपने कब्ज़े में ले ली थी। मुशर्रफ हर हाल में चोटियों को वापिस लेना चाहता था।

पाकिस्तानी पत्रकार नसीम ज़हरा अपनी पुस्तक "फ्रॉम कारगिल टू द कॉपः इवेंट्स डैट शूक पाकिस्तान" में लिखती हैं कि कारगिल की योजना कई सालों से विचाराधीन थी, लेकिन इसे 1999 में पूरा किया गया। यह योजना जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ ने बेनजीर भुट्टो के सामने पेश किया था। उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इससे पहले जनरल जियाउल हक़ के समय में भी इस पर बात हुई थी। नसीम ज़हरा के इस पुस्तक के अनुसार पाकिस्तान की योजना कश्मीर में पहाड़ की कुछ चोटियों पर कब्ज़ा करने और फिर श्रीनगर-लेह राजमार्ग को बंद करने की थी। इस सड़क को बंद करना पाकिस्तान की प्रमुख रणनीतियों में शामिल था क्योंकि यह एक मात्र रास्ता था जिससे भारत कश्मीर में तैनात सैनिकों को सैन्य हथियार भेजता था। भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में नसीम जहरा आगे लिखती हैं कि भारतीय सैनिकों के द्वारा किये जाने वाले हमले इतने भयानक और सटीक थे कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों का 'चूरा' बना दिया था।

1971 के युद्ध में मुंह की खाने के बाद लगातार छेड़े गए छद्म युद्ध के रूप में पाकिस्तान ने ऐसा ही छद्म हमला कारगिल में 1999 के दौरान किया। तीन मई 1999 को जब स्थानीय गड़ेरियों ने पाकिस्तानी घुसपैठ की सूचना हमारे जवानों की दी थी, उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर इतना बड़ा भीषण युद्ध होगा। घुसपैठ की सूचना पर भारतीय सेना का गश्ती दल जब वहां पहुंचा तो उन आस्तीन के सांपों ने हमारे पांच सैनिकों को बंधक बना लिया और यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया। एक जून को पाकिस्तान ने एनएच-1 पर बम बरसाने शुरू भी कर दिये थे। जब 6 जून को भारतीय सेना के द्वारा जोरदार जवाबी हमला किया गया तो पाकिस्तान के पांव उखड़ गये। 6 जून के बाद भारतीय सेना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते गये। पहले बाल्टिक सेक्टर की दो अहम चौकियों पर कब्जा, फिर द्रास में तोलोलिंग पर कब्जा... और यह क्रम बढ़ता गया। 18 हजार फीट की ऊंचाई पर कारगिल का यह युद्ध तकरीबन दो माह तक चला, जिसमें 527 वीर सैनिकों को बलिदान देना पड़ा। 1300 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में घायल हुए। पाकिस्तान के लगभग 1000 से 1200 सैनिकों की इस युद्ध में मौत हुई।

भारतीय सेना के लिए कारगिल का यह दुर्गम क्षेत्र मात्र एक चोटी ही नहीं थी यह तो करोड़ों देशवासियों के सम्मान की चोटी थी। भारतीय जवानों ने डट कर पाकिस्तानी हमले का जवाब दिया। एक - एक कर कारगिल की चोटियों को खाली कराया जाने लगा। 13 जून, 1999 को तोलोलिंग चोटी को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ा लिया, जिससे आगे के युद्ध में उन्हें बेहद मदद मिली। जल्दी ही 20 जून, 1999 को प्वांइट 5140 भी उनके कब्जे में आने से तोलोलिंग पर उनका विजय अभियान पूरा हो गया। चार जुलाई को एक और शानदार विजय दर्ज की गई, जब टाइगर हिल को उनके कब्जे से मुक्त कर दिया गया। खदेड़ना जारी रखते हुए भारतीय सैनिक आगे बढ़ते रहे। बटालिक की प्रमुख चोटियों से पाकिस्तानी सेना को भगा कर उन्हें दोबारा भारत के कब्जे में ले लिया गया। भारत की 14 रेजिमेंट्स ने शक्तिशाली बोफोर्स से कारगिल में घुसपैठ कर बैठे पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। भारत ने एलओसी के भीतर वायुसेना के विमानों से भी हमले शुरू कर दिए। 11 जुलाई आते – आते पाकिस्तानी सैनिकों के पांव उखड़ गए और पाकिस्तानीं रेंजर्स बटालिक से भागना शुरू कर दिया। 26 जुलाई को अधिकारिक रूप से यह युद्ध समाप्त हुआ। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के पराक्रम की अनेक गाथाएं है। इस युद्ध में हमारे जवानों ने साहस और शौर्य की वह मिशाल पेश की जो भावी पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी।

Paramvirs of KARGIL War

A The year 1999 (May to July) saw India fight a Limited War with Pakistan in the Kargil region of Drass Sector. Popularly known as the Kargil War or Operation Vijay, it saw many young brave heart soldiers fight bravely to dislodge the enemy, strategically perched on snow-peaked mountains. In maneuvering the hostile terrain and scaling steep cliffs to reach the enemy posts, many had to make the ultimate sacrifice of laying down their lives in the line of duty, to protect their Motherland. Kargil saw the biggest casualty and loss of commissioned officers in any combat in the history of Independent India. About 530 Officers lost their lives and almost double that number were injured in the War. As a mark of respect, the Nation bestowed numerous military honours to the brave soldiers like PVC, MVC, VC, SC. The highest military honour of the land , the Param Vir Chakra, which was established on 26th January 1950 was given to 4 deserving heroes, who's brief biography we will study in this article.

Picture of Indian Soldiers displaying the tricolor after successfully capturing Tiger Hills. **26 July** is celebrated as **Vijay Diwas**, to commemorate the victory in **Operation Vijay**

Captain. Manoj Kumar Pandey

Born in Sitapur Uttar Pradesh, he was the eldest child of a middle class family. He was an avid sportsman since childhood. Fired by the zeal to serve his Motherland, he joined NDA. After graduating from NDA, he joined the Gorkha Rifles. He was destined to win the PVC as he mentioned in his Service Selection Board (SSB) interview during the course of his Entrance Examination for the NDA that he wanted to join the Army to win the PVC. Posted in Kargil during the War, Captain Pandey was assigned the task of clearing the strategic, Jubar Top. On the night of 23rd July, he along with his platoon, waged an attack to clear Jubar Top. While still on a narrow ledge, they were attacked by the enemy forces. Instead of turning back, he showed exceptional courage and encouraged his men with a loud battle cry and charged on the enemy. He killed two enemy soldiers in a hand combat and went on to capture the point. However, due to critical bullet wounds, he laid down his life in the line of duty.

Captain. Vikram Batra

Born into a humble middle class family in Palampur, Himachal Pradesh, Vikram Batra made it to the Indian Military Academy (IMA), Dehradun in 1996 at the young age of 22. Commissioned in the Jammu and Kashmir Rifles, he was sent from sub sectors of Drass and Batalik to capture the important peak point 5140. Nicknamed Sher Shah, he along with his Delta Company decided a surprise attack on the enemy from the rear. As they approached the top of the steep cliff, the enemy noticed their movement and started heavy firing from the peak top on them. Despite the imminent danger to life, his battalion kept moving ahead under his able guidance from the front. They destroyed the enemy machine gun post by hurling grenades. Despite being grievously injured he inspired his team to victory. Point 5140 was captured at 3.30am on 20th June. But a braveheart laid down his life in the process. In recognition of his courage in the face of death, Captain Vikram Batra was honoured with the Highest Gallantry Award, the PVC posthumously.

Naib Subedar Yogendra Singh Yadav

Hailing from Buland Shahar District of Uttar Pradesh, he served in the 18 Grenadiers regiment. His platoon was part of the Ghatak Task Force that was given the mission of capturing three bunkers on Tiger Hill. On the morning of 4th July, 1999 at the height of 16,500 feet, the platoon was to reach the top of a snow covered mountain. He volunteered to fix the rope for the soldiers to reach the top. While accomplishing his task, he was fired upon by machine guns and rockets and sustained bullet wounds on his groin and shoulder. Despite the injuries, he reached the top and killed four Pakistani soldiers in a hand combat and put an end to the machine gun fire. His exemplary grit and determination inspired his fellowmen to wage a victorious war in an extremely critical situation.

Rifleman Sanjay Kumar

Born in Bilaspur, Himachal Pradesh, Sanjay Kumar joined the Jammu and Kashmir Rifles and was posted in the region at the time of Kargil War. He was given the task of capturing Area Flat Top of Point 4875 in the Mushkoh Valley on 4th July, 1999. After reaching the top of the cliff, they were faced with fire from a machine gun only 150 metres away. Assessing the danger, he crawled up the ledge and charged towards a bunker all alone. He was hit in the chest and forearm and started bleeding profusely yet he did not stop or give up. He managed to kill three soldiers in hand combat and 4 more in a second bunker by firing at them with his machine gun. His act of bravery inspired his platoon, to capture Area Flat top.

लद्दाख में स्वदेश निर्मित इन्फ्रेंट्री प्रोटेक्टिड मोबिलिटी व्हीकल्स की तैनाती, दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने में होगी आसानी

भारत – चीन सीमा पर बीते दो वर्षों से तनाव जारी है। सीमा पर निगरानी रखने और त्वरित कार्रवाई के लिए भारतीय सेना लगातार अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रही है। भारतीय सेना नित नये तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमता ((Artificial Intelliegence-AI) से लैस होते दिख रही है। इसी बीच बीते दिनों स्वदेश निर्मित इन्फ्रेंट्री प्रोटेक्टिड मोबिलिटी व्हीकल्स (आईपीएमवी) को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। शामिल करने के साथ ही आईपीएमवी को लद्दाख में गश्ती दलों का हिस्सा बना दिया गया है। आईपीएमवी के शामिल होने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएससी) के दुर्गम इलाकों में अब भारतीय जवानों की पहुंच और ज्यादा आसान हो गई है। यह अग्रिम इलाकों में सैन्य गश्ती दलों का एक स्थाई साथी रहेगा। इसे लद्दाख सीमा पर सेना की गतिविधियों को बढ़ाने और सहायता पहुंचाने में तेजी लाने के लिए शामिल किए गए हैं। इन इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहनों को लद्दाख की घाटियों में चलने के लिए खास तरह से बनाया गया है। लद्दाख के ऐसे क्षेत्रों में जहां एक साधारण मिलिट्री वाहन से जाना असंभव है, वहां ये कॉम्बैट वाहन आसानी से सेना की टुकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जा सकते हैं। यही नहीं इन कॉम्बैट वाहनों में हथियार भी लगाए गए हैं इन्हें वाहन के अंदर बैठकर नियंत्रित किया जा सकता है।

क्या है इन्फ्रेंट्री प्रोटेक्टिड मोबिलिटी व्हीकल्स

भारत में निर्मित इन्फ्रेंट्री प्रोटेक्टिड मोबिलिटी व्हीकल्स (आईपीएमवी) एक एटीवी (ऑल टेरेन व्हीकल्स/सभी इलाकों में जाने वाला वाहन) है जो छोटे पहाड़ों, टीलों, पथरीले रास्तों, रेतीले इलाकों में उपयोग किया जा सकता है। इसे प्रति रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने टाटा समूह के साथ मिलकर विकसित किया है। इसे पूणे में तैयार किया गया है। इन वाहनों में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड (टीएएसएल) का इन-हाउस डिजाइन और विकसित रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन शामिल है। ऑनबोर्ड थर्मल साइट्स और बाहरी ऐड-ऑन कवच सुरक्षा पैनल हैं जिन्हें डीआरडीओ की डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैब द्वारा विकसित किया गया है। निजी क्षेत्र की कंपनी सभी तैनाती वाले जगहों पर वाहनों के रखरखाव के लिए हर हमेशा सहायता देगी। इन्हें सेना में शामिल करने से पूर्व लद्दाख के पर्वतीय इलाकों में इनका गहन परीक्षण हुआ है। यह पूरी तरह से बख्तरबंद हैं और लड़ाई के समय अंदर बैठने वाले सैनिकों की गोली और बम से रक्षा करने में सक्षम हैं। इन कॉम्बैट वाहनों को बुलेटप्रूफ स्टील शीट से बनाया गया है। इन वाहनों को इस साल अप्रैल में भारतीय सेना को सौंपा गया था। सेना लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में इन वाहनों का इस्तेमाल कर रही है। इस साल अप्रैल में भारतीय सेना को सौंपा गया था। सेना लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में इन वाहनों का इस्तेमाल कर रही है। सेना की उत्तरी कमान के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने इसे विधिवत रूप से थल सेना में शामिल किया है। उन्होंने खुद इस वाहन को चलाया और परखा है। उन्होंने कहा कि यह वाहन में हमारे जवानों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। कई इलाकों में हमारे जवानों को पैदल ही गश्त करने जाना पड़ता था और इसमें बहुत समय लगता है।

इन्फ्रेंट्री प्रोटेक्टिड मोबिलिटी व्हीकल्स (आईपीएमवी) की विशेषता

इन्फ्रेंट्री प्रोटेक्टिड मोबिलिटी व्हीकल्स अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इस वाहन में दूरबीन लगाए गए हैं जिससे अंदर बैठा सैनिक 1,800 मीटर तक की दूरी तक देख सकता है। आईपीएमवी की मदद से वह अब दिनों की दूरी चंद घंटों में पूरी करेंगे। यह वाहन लद्दाख के अग्रिम इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल है। आईपीएमवी की छत के ऊपर हथियार भी लगाए जा सकते हैं, जिन्हें भीतर बैठा जवान आसानी से संचालित करते हुए अपने दुश्मन पर सटीक प्रहार कर सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सेना को मेड इन इंडिया वाहनों की आपूर्ति करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। मौजूदा समय में कॉम्बैट वाहनों के लिए भारतीय सेना की निर्भरता रूस और अमेरिका में बने वाहनों पर अधिक है। हालांकि, अब मेड-इन-इंडिया अभियान के तहत देश की कई कंपनियां सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए सामने आ रही हैं।

New strategic alignments presuppose new trade routes

| K N Pandita |

Partition of India in 1947 and the emergence of an endemic hostile state to our west have impeded the full growth of our strategic, commercial and cultural relations with the West Asian neighbours. Nevertheless, the imperative of widening trade relations and realignment of security strategies necessitated India finding an alternative road - cum - sea link to Afghanistan, Central Asian countries and further north to the Russian Federation and finally the Eastern European countries.

Conscious of the need for viable connectivity India took an initiative in that direction. Some of the countries in the region envisioning stakes in new connectivity also considered sharing India's initiative. Afghanistan, Iran, Central Asian States and the Soviet Federation are the likely partners in this big endeavour.

For a long time, Afghanistan went on struggling for an independent and self-reliant regime in Kabul. Its people had to go through fire and brimstone while realizing their dream and get rid of external interference. Now that the Taliban have achieved the objective, by a strange quirk of destiny it has to face a wily opponent who embrace the extremist ideology that poses serious threat to the Taliban regime. It is called the ISIS-K and K stands for the provinces of Khorasan.

ISIS-K is the Afghanistan affiliate of Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). It emerged in 2015. The group's aims and declared geography of operations were very broad. Advocating for mass-casualty attacks against civilians and states, "the group intended to topple the Pakistani government, punish the Iranian government for being a "vanguard" of Shias, and "purify" Afghanistan — both by dislodging the Afghan Taliban as the main jihadi movement in Afghanistan and punishing minority groups, like the Hazaras", wrote Asfandyar Mir of the Wilson Centre in the Insight and Analysis of 8 October 2021.

The main cause remains their sectarian difference. ISIS-K subscribes to the Jihadi-Salafism ideology, and plays up the 'purity' of its anti-idolatry credentials. The Taliban, on the other hand, subscribe to an alternative Sunni Islamic sectarian school, the Hanafi madhhab, which ISIS-K regards as deficient. The two groups also differ over the role of nationalism. ISIS-K fiercely rejects it, which runs counter to the Afghan Taliban's aims of ruling over Afghanistan.

Political stability of Afghanistan being largely tenuous, the broad parameter for overland route connecting India with the East European region had to be given a close and serious thought. The outcome was the International North-South Transport Corridor (INSTC) aiming at increasing trade between India and Russia. This trade route is 7200 Km long and the transport of freight is through a multi-mode network of roads, ships, and railways. This route connects India and Russia through Iran and Azerbaijan.

The earlier trade route connecting India and Russia was through the Suez Canal. It is a long route. Hence the major objective of the INSTC corridor was to reduce the time taken, costs incurred, and increase connectivity between major cities like Mumbai, Moscow, Astrakhan (located in Russia), Baku (Azerbaijan), Tehran, Bandar

Abbas and Bandar Anzali (all located in Iran). Following are the main considerations that led to the endorsement of the project by the relevant countries named above.

- The corridor is aimed at reducing the carriage cost between India and Russia by about 30% and bringing down the transit time from 40 days by more than half.
- It could be considered as a very important corridor for the development of freight traffic in the region.
- This corridor is capable of boosting India's economy. Indian exports are expected to increase substantially during the next calendar year.
- This corridor is expected to increase market access to the member nations who can also benefit through various backward and forward linkages.

The trial of transporting Russian goods from Astrakhan to a southern Iranian port to its destination at Mumbai's Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) under the INSTC Corridor, marks the baby steps toward India joining an emerging Russia-Iran-India trade and security axis.

On Jun 8, Iranian foreign minister Hossein Amirabdollahian was in New Delhi on an official visit to discuss various issues of common interests. This was also the time when the unfortunate incident happened in India in which two BJP members had to be expelled from the party for alleged indiscreet remarks that had offended a large number of Islamic states including Iran. We expected that the incident would throw cold water on the agenda for which the Iranian delegation had arrived in India. But giving an enviable proof of his political maturity and the sincerity of intentions, the Iran Foreign Minister clarified his position by saying that the official statement of the GoI that it respected all religions, was good enough to reassure everybody that India was a secular democratic state and had to be respected thereby.

As the trial for smooth transportation of Russian timber was set in motion and Iran's FM had pacified the tense situation, simultaneously a call between Russian President Vladimir Putin and Iranian President Ebrahim Raisi took place the same day.

Part of the International North-South Transport Corridor (INSTC) to connect Russian, Iranian and Asian markets, can be seen in the broader context of shifting alliances and pragmatic normalizations – forced mainly by the economic vagaries of a Covid economy and anti-Russia sanctions.

This is the background for India evincing keen interest in developing Chahbahar sea port in the Persian Gulf. The Indo-Iranian Chahbahar agreement came under a cloud owing to the sanctions imposed by the Trump government on Iran in 2020. The project seemed to be running into the doldrums. Iran threatened to invite China to take control of Chahbahar development. Iran even withdrew its consent to Indian Railways working on rail connectivity to Afghanistan and then to Central Asia.

However with the change of regime in the US, the conciliatory role of the European countries towards Iran and resumption of Iran nuclear talks all contributed to a re-think over Indo-Iran relations and then the revision of Iran's Chahbahar policy.

India declined to endorse the UN anti-Russia resolution on Ukraine. Ever since, the US – Indo relations have become partly sour. Though India declined to sign for her own reasons, it was not an act of vendetta against Ukraine which has usually served a proxy of the US and the Western bloc to do some arms twisting of India at the United Nations. India's denial of towing the American line is essentially a signal to the US and the EU countries to change their mindset. That is what the Indian foreign minister bluntly told his British counterpart that the world had

change and India was the India which the colonialists had projected to the world. There was loud talk at one time of the US imposing sanctions on India for not signing the anti-Russia resolution and for signing oil deal with Moscow. It proved a damp squib.

India is dealing with the Afghan Taliban regime with pragmatism. The Taliban have told Indi to reopen her embassy and promised to provide protection to the Indian staff and citizens. Iran has shown renewed interest in Indo-Iranian project of Chahbahar and the related rail connectivity. India has established very cordial relations with Tajikistan, the so-called underbelly of the erstwhile Soviet Union but of immense strategic importance in the region. The only Central Asian Republic which declared it would resist any move northward by the Afghan Taliban during their crucial fight with the Americans in Afghanistan. The five Central Asian Republics are on board. As such great hopes are pinned to strong overland commercial and security interests for all stakeholders in the region.

Some commentators talk of India-Iran-Moscow axis. Others include China in the axis. The reality is that India does not frame her foreign policy of forming blocs and groups and axis's etc. The entire narrative is about the awakening among the developing countries and its fallout. The Western world shall have to take note of it and modify their policy towards the Third World accordingly.

राजस्थान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का हंगामा, नवनिर्मित पुस्तकालय को खोलने की मांग

प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जमकर हंगामा देखने को मिला है। ये मामला है राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में स्थित नए पुस्तकालय को तुरंत प्रभाव से शुरू करने के लिए। पुस्तकालय के सामने अभाविप के नेतृत्व में छात्रों के प्रदर्शन के बाद अचानक इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। मौके पर मौजूद अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा पुस्तकालय का ताला-तोड़कर छात्रों को अंदर प्रवेश करवाया गया।

गौरतलब है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में बन रहा नया पुस्तकालय को बनकर तैयार हुए करीब तीन साल से अधिक समय बीत चुका है। राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए विश्वविद्यलय परिसर में करीब 5 साल पहले इस पुस्तकालय की नींव रखी गई थी। करीब दो साल के निर्माण कार्य के बाद छोटे-छोटे कामों के चलते पुस्तकालय का काम अटका हुआ दिखा लेकिन पिछले करीब दो सालों की बात की जाए तो पुस्तकालय पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुस्तकालय के उद्घाटन को लेकर तीन बार घोषणा भी की जा चुकी है लेकिन हर बार उद्घाटन की तिथि में बदलाव ही होता गया, जिसके चलते अब छात्रों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है।

अभाविप ने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ प्रदर्शन करते हुए पुस्तकालय का ताला तोड़ा है। अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने बताया कि पुस्तकालय का काम हुए करीब तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, दो साल से सिर्फ तिथि ही जारी हो रही है लेकिन उद्घाटन नहीं हो पाया रहा है, जिसके चलते राजस्थान विश्वविद्यालय के आम छात्रों की मौजूदगी में पुस्तकालय का ताला तोड़ा है। पुस्तकालय छात्रों कों ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की राजनीति के चलते इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा है।

मुद्दा : नेशनल हेराल्ड घोटाला

कानून के शिकंजे में कांग्रेस नेतृत्व

| संजीव कुमार सिन्हा |

नेशनल हेराल्ड घोटाला सुर्खियों में बना हुआ है। अवैध तरीके से किस प्रकार संपत्ति हड़पी जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण बन गया है यह घोटाला। इस मामले में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है और इस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वे दोनों भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और 2015 से जमानत पर बाहर हैं। दोनों कांग्रेस नेताओं को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है।

क्या है यह मामला?

वर्ष 1937 में एक कंपनी के रूप में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की स्थापना हुई। जवाहरलाल नेहरू ने पांच हजार स्वतंत्रतासेनानियों के साथ एजेएल की शुरुआत की थी। इस कंपनी द्वारा तीन समाचार-पत्रों- अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ का प्रकाशन होता था। इसका उद्देश्य था अखबार के माध्यम से आजादी की लड़ाई को तेज करना। लेकिन आजादी के बाद ये अखबार कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र बन गए। एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई, पंचकूला, लखनऊ और पटना में प्राइम लोकेशन पर अरबों की प्रॉपर्टी थी। वर्ष 2008 में एजेएल के सभी प्रकाशनों को बंद कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपये का कर्ज भी चढ़ गया। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी का गठन हुआ। इस कंपनी में 38 प्रतिशत हिस्सेदारी सोनिया गांधी की थी और 38 प्रतिशत हिस्सेदारी राहुल गांधी की। बाकी बची 24 प्रतिशत हिस्सेदारी गांधी परिवार के करीबियों मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के नाम थी। 2011 में कांग्रेस ने इस कंपनी को बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जबकि कोई राजनीतिक दल किसी को कर्ज नहीं दे सकता। इस 90 करोड़ रुपए के कर्ज से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2,000 करोड़ रुपए की स्वामित्व वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को खरीद लिया। इसके बाद यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपये कांग्रेस पार्टी को लौटा दिया। बची हुई 89 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि कांग्रेस ने माफ कर दी। इस तरह कांग्रेस नेतृत्व द्वारा नियम-कानून को ताक पर रखते हुए स्वंत्रतासेनानियों की पूंजी को हड़पा और पार्टी फंड का दुरुपयोग किया गया।

कैसे आया यह मामला प्रकाश में

नेशनल हेराल्ड मामले में साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निचली अदालत के समक्ष अर्जी दी थी। स्वामी का कहना था कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में कुछ कांग्रेस के नेता धोखाधड़ी और विश्वासघात में शामिल थे। यंग इंडिया लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके से हड़प लिया था। इस मामले में स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, पत्रकार सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को नामजद किया।

सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 2 हजार करोड़ रूपए से अधिक संपत्ति को

अवैध तरीके से अधिग्रहित किया। यंग इंडिया लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान किया था, जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। यह राशि अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दिया गया कर्ज अवैध था, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था।

दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में चार गवाहों के बयान दर्ज किए थे। 26 जून, 2014 को अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित नई कंपनी में निदेशक बनाए गए सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा को पेश होने का समन भेजा था।

राजनीतिक दलों के मंतव्य

कांग्रेस ने इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि पार्टी ने यंग इंडिया लिमिटेड को दान के उद्देश्य से बनाया था न कि किसी लाभ के लिए। कांग्रेस ने बताया कि लेन-देन में किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं की गई है। क्योंकि यह कंपनी के शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए केवल एक कॉमर्शियल लेनदेन था। पार्टी ने स्वामी द्वारा दायर की गई शिकायत पर भी आपत्ति जताई और इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया।

भाजपा का कहना है, "यह मामला यूपीए सरकार में सामने आया। उच्च न्यायालय के आदेश पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत लेनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी के अन्दर की संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हिंसा का भी सहारा लेने में किसी भी प्रकार की कोई झिझक नहीं हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक परिवार की पार्टी बनकर रह गयी है।"

ईडी ने की पूछताछ

2014 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले का संज्ञान लिया और धन शोधन का केस दर्ज किया था। तबसे इस मामले में लगातार प्रक्रिया चलती रही है। जून 2022 में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। हालांकि इन दोनों ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी, लेकिन दोनों ही जगहों से इन दोनों को राहत नहीं मिली। बाद में सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गईं और तब उन्होंने ईडी से तीन हफ्ते का समय मांग लिया। वहीं, राहुल गांधी से ईडी ने लगातार पांच दिनों तक लगभग पचास घंटे पूछताछ की।

कांग्रेस का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया

आज देश में कांग्रेस बुरी स्थिति में है। वह एक के बाद एक लगातार चुनाव हार रही है। उसकी जमीनी पकड़ कमजोर हो रही है। उसके नेता-कार्यकर्ता न तो अपने संगठन को मजबूत करने में सक्रियता दिखा पा रहे हैं और न ही किसी जनहित के मुद्दे पर लामबंद हो पा रहे हैं। लेकिन नेशनल हेराल्ड प्रकरण में अवैध तरीके से धन हस्तांतरण मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पार्टी नेताओं को नागवार गुजर रही है। वे इसे राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताकर आगबबूला हो गए हैं। जबकि यह मामला 2012 में कांग्रेसनीत यूपीए के शासनकाल में

शुरू हुआ। किसी सरकारी एजेंसी द्वारा इस मामले की जांच की शुरुआत नहीं की गयी बल्कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई हुई। इस सबके बावजूद कांग्रेस शासित राज्य के दो मुख्यमंत्रियों, अन्य राज्यों से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली बुलाया गया। वे चक्का जाम, आगजनी आदि का सहारा लेकर लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस डर क्यों रही है? कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जांच एजेंसी पर दबाव डालना गलत है। यह भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

भ्रष्टाचार पर चोट

कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार प्रशासन का जरूरी हिस्सा बन जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार जब दिल्ली से एक रुपया भेजती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। यानी 85 पैसे भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते थे। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। यानी हमारे देश में भ्रष्टाचार प्रमुख समस्या बन गई थी। लंबे समय तक यह संस्थागत रूप में बना रहा। लोग हताश-निराश हो गए थे। उन्हें लगता था कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ऊंचे पदों पर आसीन एवं रसूखवाले व्यक्ति भ्रष्टाचार करके भी बचे रहते थे। लेकिन 2014 में व्यवस्थागत बदलाव हुआ। भाजपानीत राजग सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार कर रही है। मोदी सरकार की स्पष्ट नीति है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस। यदि कोई भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उसके विरुद्ध तेजी से कार्रवाई होती है।

राष्ट्रीय कला मंच द्वारा सिरोही में 'इंद्रधनुष' कार्यक्रम का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जोधपुर प्रांत के द्वारा राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से सिरोही में इंद्रधनुष 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक रेखा माली ने इंद्रधनुष कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में परिषद द्वारा मेहन्दी, रंगोली, चित्रकला, गायन, पारम्परिक वेशभूषा एव नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छः नगर इकाई के 138 से छात्राओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कला मंच द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले छात्राओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव आज पूरा देश मना रहा है, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी उतनी ही है, जितनी अन्य सभी की है। राष्ट्रहित में महिलाओं का योगदान सहरानीय है। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना व समाज नाम रोशन कर रही है । समारोह के विशिष्ट अतिथि अभाविप जोधपुर प्रांत संगठन मंत्री पूरण सिंह शाहपुरा रहे। उन्होंने बताया की विद्यार्थी परिषद अपनी विभिन्न गतिविधियों एवं आयामों के माध्यम से समाज जीवन मे पिछले 74 वर्ष से अनवरत कार्य कर रही है, कला से लेकर खेल तक, पर्यावरण से लेकर सेवा तक हर क्षेत्र के लिए विद्यार्थी परिषद अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। विद्यार्थी परिषद केवल महिलाओं के अधिकार की बात नहीं करती बल्कि इसका अनुपालन भी करती है। उन्होंने कहा कि जिन्हें यह लगता है कि विद्यार्थी परिषद भी अन्य छात्र संगठनों की तरह केवल आंदोलन, प्रदर्शन व छात्रसंघ चुनावों तक सीमित है उन्हें इंद्रधनुष जैसे रचनात्मक आयोजन को देखना चाहिए।

डीलिस्टींग-डीलिस्टींग, बस ! एक ही नारा डीलिस्टींग

धर्मान्तरित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने के लिए मुखर हुआ समाज

। शरद चव्हाण ।

वर्तमान में देश के जनजाति क्षेत्र में और विशेषतः पांचवीं अनुसूची के राज्यों में सभी जगह एक ही मांग सुनने को मिल रही है – डीलिस्टींग, डीलिस्टींग, डीलिस्टींग। क्या है यह डीलिस्टींग ? डीलिस्टींग यानी जो जनजाति व्यक्ति स्वधर्म -संस्कृति, रीति-रिवाज, देवी-देवताओं की पूजा पद्धति, पूरखों के ऊपर आस्था छोड़कर ईसाई या मुस्लिम बनता है उसका नाम जनजाति सूची से हटाना है। यह प्रश्न गत 70 सालों से चलते आ रहा है । कांग्रेस के तत्कालीन सांसद सदस्य रहे स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने 1967 से ही इस विषय का अध्ययन करते हुए इसको सूची से हटाने हेतु प्रारंभ किया था । वर्तमान झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे स्व. कार्तिक उरांव ने 1967 से लेकर 1970 के दरमियान डीलिस्टिंग विषय को धारा 341 के तहत 342 में भी सुधार करने हेतु 348 सांसद सदस्यों के हस्ताक्षरित ज्ञापन तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सौंपा था । बता दें कि इस विषय पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में भी बहस होते हुए यह प्रस्ताव लगभग सुधार करने ही शेष रहा था, तभी 1970 में लोकसभा को विसर्जित कर दिया गया और यह विषय अधूरा रह गया।

जनजाति समाज के न्याय एवं अधिकार के लिए संपूर्ण देश भर में लोकतांत्रिक मार्ग से लड़ने तथा इसके हित की आवाज उठाने हेतु जनजाति सुरक्षा मंच का गठन 2006 में किया गया । स्व. कार्तिक उरांव जी के उपरोक्त अधुरे मांग को लेकर फिर एक बार देश भर में जागरण प्रारंभ हुआ और धारा 342 में सुधार करने हेतु 28 लाख लोगों का हस्ताक्षरित ज्ञापन वर्ष 2009 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल को दिया गया। 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है । पुनः एक बार जनजाति सुरक्षा मंच ने इस विषय को लेकर सड़क से संसद तक तथा ग्राम सेवक से सांसद सदस्य तक संपर्क अभियान प्रारंभ किया है ।

डीलिस्टींग की मांग को लेकर भरी घूप में हज़ारों की संख्या में महिला-पुरूष एकत्रित हो रहे है। अपने परम्परागत वेश में, ढोल-ताशें के साथ-कहीं सभा, कहीं सम्मेलन और रैलियां हो रही है। पत्रकार वार्ताएं भी हुई। समाज में जो जागरण हो रहा है उसका मानो एक ही संदेश है कि अब संविधान ने दिए अपने अधिकार लेकर ही रहेंगे। डिलीस्टींग आंदोलन का नेतुत्व कर रहा है जनजाति सुरक्षा मंच।

जनजाति सुरक्षा मंच का मत है कि भारत की जनजाति को उनका हक मिलना चाहिए। जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों को हथियाने वाले ऐसे गलत एवं षड़यंत्रकारी धर्मांतरित व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालीन कार्यवाही हो। जनजाति वर्ग के साथ हो रहे इस अन्याय की लड़ाई में शहर से लेकर ग्राम पंचायत तक सामाजिक पदों पर बैठे प्रतिनिधि धर्मांतरित व्यक्तियों को बेनकाब कर हटाया जायें। धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया जाये। अगर जनजाति धर्म संस्कृति, सभ्यता, मान्यता को जीवित रखना है तो स्वधर्म को जीवित रखना होगा। इसलिए रैलियों में जो स्वर सुनने को मिल रहा है कि जो न हमारे भोलेनाथ का - वो न हमारी जात का - यह

सटीक लगता है। यदि संस्कृति की बात है तो हम हमारी श्रद्धा को उससे अलग नहीं कर सकते।

वर्षों पूर्व इस प्रकार से धर्मान्तरित व्यक्तियों को जनजाति सूची से दूर करने हेतु सन 1967-70 तक प्रयास हुए थे। जनजाति नेता स्व. कार्तिव उरांव ने तत्कालीन सांसदों के हस्ताक्षर लिए थे। संसद में उसी समय निर्णय हो जाता तो आज ये दिन न देखने पडते। परन्तु उस समय समस्या को टाला गया और समय के साथ विषय ठण्डे बस्ते में चला गया। वर्षों पश्चात जनजाति सुरक्षा मंच ने फिर से प्रयास प्रारंभ किए है। मंच द्वारा आयोजित रैलियों में समाज का सहयोग हम देख सकते है। न केवल रैलियों में अपितु मंच से भाषण करने में भी महिलाओं की उपस्थिति ध्यान आकर्षित कर रही है। माता-बहनें जुड़ गई तो समाज में उत्साह देखने को मिल रहा है।

सभी रैलियों में जनजाति समाज का नेतृत्व मंच से अपनी बात कह रहा है। साथ में वन-क्षेत्र के संत-महात्मा भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह लेख लिखने तक देश भर में 130 से अधिक रैलियां हो चुकी है जिसमें 2.50 लाख से अधिक जनता उपस्थित हुई है। अगले कुछ दिनों में और अधिक जिलों में रैलियों का आयोजन होने जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 342 के नियमों में उचित संशोधन कर धर्मान्तरित लोगों को आरक्षण सूची से डीलिस्टिंग की मांग उठाई। हम समाज को एक रखने का काम कर रह हैं। ऐसे में समाज को बांटने वाले हमारे विरोधी आज वन क्षेत्र से लेकर नगर-महानगरों तक सर्वत्र भ्रम फैलाने का काम कर रहे। समाज में चल रहे इन षड्यंत्रों के पीछे के उद्देश्य को समझना होगा। अपने विरोधियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देने तक प्रयास किए। समाज विघातक तत्व इसे गलत दिशा में ले जाना चाहते है। वे मतान्तरण पर चर्चा कर रहे है। मतान्तरण क्यों हो रहा है ?, वह सही है या गलत यह वर्तमान में हमारा विषय नहीं है। हम तो बस इतना ही कहते है कि जिस किसी कारण से जो भी व्यक्ति धर्मान्तरित हो गया उसे जनजाति की सूची से हटाओ। मन्तातरित व्यक्ति जनजाति समाज की परम्परा, रिती-रिवाज को मानते नहीं, पुरखों के बताए मार्ग पर चलना चाहते नहीं, उन्हें हम जनजाति व्यक्ति कैसे कहे ? वे जनजाति के हो ही नहीं सकते। इसलिए उन्हें जनजाति की सूची से दूर करना चाहिए।

जनजाति सुरक्षा मंच की इस एक सूत्रीय मांग को वन, ग्राम से लेकर नगर-महानगरों तक और सड़क से लेकर संसद तक समाज को एक साथ मिलकर इस लड़ाई लड़ना होगा, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ीयां हमें कभी माफ नही करेगी। कई जनजाति ग्रामसभा द्वारा इस सन्दर्भ में प्रस्ताव भी पारित हुए है। स्थानीय मीडिया ने पन्ने भर-भर के समाचार छायाचित्रों सहित प्रकाशित किए। सोशल मीडिया में भी इसकी चर्चा बहुत बड़ी मात्रा में हो रही हैं। जनजाति – गैर जनजाति, सम्पूर्ण भारत का जनमानस अर्थात सभी भारतीय इस बात को समझे और मंच के आंदोलन को सहयोग करें यह समय की आवश्यकता है।

सृजनशीलता के साथ राष्ट्र प्रथम का भाव सिखाती है अभाविप : साक्षी सिंह

छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पिछले एक महीने से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बिहार प्रांत के दरभंगा इकाई द्वारा चलाए जा रहे सर्जना निखार शिविर का समापन पांच जुलाई को हुआ। समापन समारोह की मुख्य अतिथि अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह थीं। सर्जना निखार शिविर के समापन समारोह में विविध विधाओं से सजी प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात् समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् सदैव से ही छात्र-छात्राओं की अंतर्निहित प्रतिभा को निखारने तथा उनके अंदर के राष्ट्रभाव को जागृत व प्रकट करने का अवसर देते रही है। युवाओं की शक्ति को रचनात्मक गतिविधियों में लगाकर राष्ट्र हित के लिए तैयार करने वाला विश्वविद्यालय है विद्यार्थी परिषद्। जहां एक तरफ 'मिशन साहसी' के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने लाखों छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने व आत्मविश्वास पैदा करने में सफलता पाई है वहीं ऋतुमती अभियान के माध्यम से महिला स्वास्थ्य के लिए मुहिम चला रखा है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय से निरपेक्ष होकर अभाविप सदैव ही राष्ट्र प्रथम का भाव सिखाने वाले संगठन का नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्।

विशिष्ट अतिथि कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. शशिनाथ झा ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों से अभाविप दरभंगा के द्वारा सतत् रूप से आयोजित होते आ रहे 'सर्जना निखार शिविर' की सराहना की तथा प्रशिक्षकों को जामवंत तो शिक्षार्थियों को हनुमान की संज्ञा दी। कला को ईश्वर की कृति बताते हुए प्रशिक्षित छात्राओं के कला प्रदर्शन व प्रदर्शनी की उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की। कार्यक्रम में विषय प्रवेश कराते हुए प्रदेश सह मंत्री पूजा कश्यप ने कहा कि विगत 15 वर्षों

से पूरे भारत भर में दरभंगा इकाई के कार्यक्रम सर्जना निखार शिविर की चर्चा होती है। पूरे एक महीने तक चलने वाले इस शिविर में छात्राओं के अंदर की प्रतिभा को निखारने के साथ-साथ उनको विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पिछले 2 वर्ष में इस शिविर का आयोजन नहीं हो पाया था। पुनः शुरू हुए इस शिविर में सैकड़ों छात्राएं हिस्सा ली हैं।

विभाग संयोजक उत्सव परासर ने बताया कि 2 वर्षों के बाद आयोजित हो रहे इस शिविर में पूरे उत्साह के साथ छात्राओं ने भाग ली। कार्यक्रम का संचालन जिला संयोजक हरिओम झा तथा नगर सह मंत्री अणिमा सिन्हा ने किया। समापन समारोह में विविध विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली दर्जनों छात्राएं अपने संगीत, नृत्य, पेंटिंग, सिक्की आर्ट, भाषण कला, समाचार लेखन आदि कौशल का प्रदर्शन की तथा अपना अनुभव प्रकट किया। कार्यक्रम में विविध विधाओं का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों यथा आरबी ठाकुर, अनुराधा लाला, मोहित पाण्डेय, श्रेया सिंह, ए के झा, प्रजेश कुमार झा, राहुल सिंह, अनामिका कुमारी, आंचल कुमारी, सत्येन्द्र झा, विशाल कुमार, संतोष दत्त झा आदि को सम्मानित किया गया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन नगर मंत्री सूरज ठाकुर ने किया।

Call for Swaraj in the Khasi Hills

| Anandita Singh |

On the 187th death anniversary of U. Tirot Singh- a warrior from the Khasi community of present-day Meghalaya, this article aims to explore his patriotic realization, and the untouched aspects of history, his persona and the driving forces of Swadharma, Swadeshi and Swaraj that led to the freedom struggle of Khasi Chiefs against the British.

Introduction

The Khasi hills of the present-day Meghalaya was traditionally divided into 11 administrative centres (that was later increased to 25 by the British), each individually governed by an independent chief (Syiems/sardars). One among these many administrative centres was Nongkhlow (Situated approximately 60 kms North-west of Shillong). It was a crucial nodal point on the trade routes that were used by the inhabitants of Khasi hills who were mainly proficient in trade, extraction of ore, and production of iron artifacts. The regions of Khasi hills, in itself was very rich in the natural ore mines; minerals like coal, iron and limestone were abundant. But most importantly, it was a strategically important place as it gave an easy and clear passage that could connect the Surma Basin (Present day Sylhet district of Bangladesh) to the Brahmaputra Basin (Present day Assam state of India). It was due to these lucrative prospects that the money-minded, capitalist British wanted absolute control over this region and used stringent methods for the same. In 1823, David Scott, agent to the Governor General of Bengal in the North-eastern frontier, proposed a strategy of direct intervention and coercion to be adopted by the British in their engagements with the local populace. This direct intervention had a manifold and adverse effect on the people of the Khasi hills; they were exploited and left economically and socially handicapped. The events that unfolded in this region over a period of merely 6 years will showcase not just how powerful time is but how deceitful and shrewd the British were.

Background

In their desperate attempt of capturing and capitalizing all that the Khasi Hills and her people could offer, the British went on a spree of battles and forced agreements that the locals seemed to be bound to accept as their fate. On 30th November 1826 a treaty was signed between the East India Company and U. Tirot Singh, the chief of Nongkhlaw. Even a quick look at this treaty (as published in "A Collection of Treaties, Engagements, and Sanads Relating to India and Neighbouring Countries" complied by Charles Umpherston Aitchison) would

make it absolutely clear that this treaty was a warrant of oppression and no leader would willingly accept such terms. For starters, the treaty made Nungklow and its dependencies ``a subject of the company". The treaty also procured free passage for the English troops through the said territory and made provisions for the construction of a road that connected the Surma Basin to the Brahmaputra Basin. Additionally, the people were bound to supply construction material at their own cost, pay tax for using the road when it was complete and work as bonded laborers for the construction work. Thus, it maybe deduced that, David Scott the architect of Khasi Hills' destruction somehow managed through either force, fraud or inducement to get U. Tirot Singh, to sign this treaty that was extremely exploitative in nature.

Role of U Tirot Singh

Abusing the clauses of the above-mentioned treaty, the British started exploiting the people economically, disturbing their trade, and committing atrocities on women. There was chaos and mayhem. It is noteworthy that the British had assumed that the chiefs of this region including U Tirot Singh worked in isolation, they would not join hands with each other thus the Britishers' hegemony would go on unchallenged. They, like always, were wrong.

Early in 1829, U. Tirot Singh realized the power that the chiefs could collectively wield. He had signed an unjust treaty under the impression of peace but seeing the large-scale exploitation of his region and people who were forced into a slavery like situation by the British who did not even consider that construction of a road can be taxing and the workers deserve payment, concluded that peace that came at such a high cost was no peace at all and could not be sustained.

He thus made plans to expel the British. He no longer considered himself bound by the treaty of 1826. On 1st April 1829, a conference of Khasis Syiems (Chiefs) was held at Nongkhlaw, hosted by U. Tirot Singh wherein it was decided to drive out the British from their land. Indigenous weapons and clandestine intelligence formed the basis of this war. Meetings were conducted wherein, under the leadership of U. Tirot Singh, plans were hatched and tough decisions made. For the local inhibitors topography and knowledge of forest-clad routes was their biggest strength. The Guerrilla warfare thus was the smartest choice for these fighters who, lacked a technically superior stock of ammunition but their courage was inferior to none!

Finally, on April 4, 1829, a group of about 500 Khasis, by a sudden yet planned attack, killed two English Officers, Lieutenants Burlton and Bedingsfield, and sixty Sepoys at their Nongkhlao post, burnt down the bungalow and released the prisoners who were kept captive by the British, being forced into slavery. War broke out that lasted for 4 years (1829-33) with Tirot Singh at the helm of commanding armies, followed by the Chiefs of Myriaw, Jirang, Rambrai, Mawsynram, Bhowal, Nongpoh, Maharam, and Mawieng. He was also joined by Monbhut as his commander in chief and Phan Nonglait, a woman warrior at the forefront.

The mere fact that the Kahsi warriors could keep the British engaged for 4 years is enough to highlight heir prowess, but in addition to that, their sense of self pride was adequately reflected in 1831 when the British tried to negotiate with U Tirot Singh, thinking he could be manipulated again but he was adamant to not agree to anything short of abandonment of the proposed road and unconditional restoration of his territory to him. In

other words, the denial to negotiate with the British at all by Tirot Singh was his call for Swaraj!

Conclusion

After constant warfare wherein the Khasi chiefs fought together for freedom, U Tirot Singh secured for himself and his people the right to a dignified life and relieved them from the exploitation that they were suffering.

Sadly, in 1831, when Tirot Singh completely rejected any form of British lordship over him, his territory and his people, the British took the longer route of weaking him. In 1831 itself they entered into agreements allegiance with Adhor Singh chief of Maosenram and Bor Manick. Thus, weakening the Position and strength of U Tirot Singh which eventually led to him being arrested. He was captured by trickery on 13th January, 1833 when the British cornered him in the jungles after having trapped him in a psychological siege by eliminating his allies one by one. He was sent to Decca jail where he was tortured, his humanitarian rights and needs neglected and eventually died a hero on 17th July1835.

U Tirot Singh's martyrdom was a beacon of hope for all those who heard about the glorious battle, they joined hands with one another and resolved to face the British. It was a wave of patriotism washing over the British, knocking them down over and over again for decades, making them incapable of gaining strong control in the region.

(Anandita Singh is a researcher at Centre for North East Studies (CNES), New Delhi. The article is based on primary documents and field visits. Author may be contacted at anandita.nec@gmail.com)

कानपुर : एचबीटीयू में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में अभाविप का प्रदर्शन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) में प्रदर्शन किया। इस दौरान परिषद कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता पर रोष जताया। इस दौरान अभाविप नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में छात्र-छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।

अभाविप कार्यकर्ताओ ने बताया कि पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय की करतूत उजागर हो रही है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। इसलिए सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन की आंख-कान खोलने का काम किया गया। परिषद कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम से अभाविप ने अपनी बात विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखी है। यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं होती तो हम आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। अभाविप ने कहा कि जिस तरह विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस को बुला कर हमारी आवाज दबाने का असफल प्रयास किया है, ऐसी गतिविधियों से उनकी दाल नहीं गलने वाली है। ना ही हमारी आवाज दबने वाली है, प्रशासन को तत्काल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जांच करा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी।

फिरोजाबाद : अवैध वसूली करने वाले विद्यालय प्रशासन के खिलाफ अभाविप ने की कार्रवाई की मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा फिरोजाबाद में विद्यालय की आड़ में कोचिंग सेंटर चलाने वाले विद्यालय संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए, बंद कराने की मांग की गई है। अभाविप कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के संबोधित ज्ञापन डीएम को देकर ऐसे विद्यालय बंद कराए जाने की मांग की है। अभाविप ब्रज प्रांत के प्रदेश सह मंत्री रजत जैन ने कहा कि शहर में चल रहे कोचिंग संस्थानों की आड़ में अवैध विद्यालय की जांच होनी चाहिए और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की भी जांच हो। साथ सरकारी अध्यापको द्वारा छात्रों को प्रक्टिकल नंबर की धमकी देकर उनके माध्यम से अपनी कोचिंग संचालित करने अध्यापिको की जांच हो। प्रान्त कार्यकारिणी सदस्य अतुल चौधरी ने बताया कि शहर में बिना मान्यता के दसवीं व बारहवीं की मार्कशीट अन्य विद्यालयो के माध्यम से उपलब्ध करने वाली कोचिंग संस्थान की जांच होनी चाहिए। वहीं प्रान्त कार्यकारिणी सदस्य राज पलिया ने बताया कि शासन द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए एक फीस गाइड लाइन होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि ये सारी जांच हमारी 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के सामने हो। जिला सह सयोजक नेहा सिंह ने कोंचिग संस्थानों के मानक पर सवाल खड़ा किए, जबकि महानगर सह मंत्री सुजल राठौर ने कोचिंग संस्थानों द्वारा संचालित बसों के फिटनेश की जांच एवं सीमित सीटों से ज्यादा छात्रों को बैठाकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने बाली संस्थानों की जांच करने की मांग की। अभाविप पदाधिकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी।

छात्रों का कर रहे शोषण

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने डीएम को मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र देकर छात्र—छात्राओं से अवैध वसूली करने वाले स्कूल संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिले के अंदर संचालित कोचिंगों की आड़ में अवैध स्कूल जो चल रहे हैं उसके संबंध में जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। बताया गया कि तमाम कोचिंग संस्थान ऐसे चल रहे हैं जो बच्चों से अवैध वसूली करके उनको फर्जी मार्कशीट देना, नौंवी दसवीं पास कराने के नाम पर लाखों रूपये लेते हैं जिस संबंध में ज्ञापन देकर यह अवैध वसूली बंद कराने की मांग की गई है।

कोचिंग पढ़ने के लिए बनाते हैं दबाव

संगठन के पदाधिकारियों ने ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ जो बच्चों पर कोचिंग पढ़ने के लिए दबाव बनाते हैं। कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिले भर में करीब दो दर्जन से अधिक ऐसे स्कूल संचालित हैं जो केवल कोचिंग का काम करते हैं लेकिन स्कूल के नाम पर बच्चों का प्रवेश लेकर उनका शोषण करते हैं। कई बार ऐसे स्कूल संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।

अभाविप कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के ऑडनकॉल पास का किया फतह, समुद्रतल से 5490 मीटर ऊंचे खतलिंग ग्लेशियर के समीप लहराया अभाविप का झंडा

| सोनी मिश्र |

उत्तर काशी : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल के कार्यकर्ताओं ने भारत की सबसे कठिन पर्वत में से एक जोगिन रेंज़ व गंगोत्री पर्वत को जोड़ने वाली 5490 मीटर ऑडन कॉल पास को फतह कर विद्यार्थी परिषद का परचम लहराया। दुर्गम चोटी पर झंडा फहराने एवं यात्रा के बारे में बताते हुए अभाविप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व पर्वतरोही अभिषेक मेहरा ने बताया कि उत्तराखण्ड सरकार की तरफ से नए-नए ट्रैक खोजे जाने व पर्यटन की दृष्टि से आयोजित एक कोर्स चलाया गया था, जिसमें परिषद के कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत मां गंगोत्री के आशीर्वाद से हुई जहां से होते हुए रुद्र-गैड़ा बेसकैंप, गंगोत्री बेस कैंप, होते हुए ऑडेन कॉल पास को फतह कर 5490 मीटर ऊंचे स्थान पर परिषद का झंडा फहराया व नारे लगाए, जिसके पश्चात खतलिंग ग्लेशियर पार करते हुए मयाली ग्लेशियर, मसार ताल वासुकी ताल होते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 150 किलोमीटर की यात्रा करने एवं बाबा केदारनाथ के दर्शन कर वापस लौटे।

कार्यकर्ताओं ने बताया कि कई बार ऐसा मंजर भी आया जब वे ग्लेशियर पर चल रहे थे और बर्फ लगातार तेजी से पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि पैर मानो जकड़ से गए हो। बर्फ इतनी अधिक थी की पैर के साथ - साथ शरीर भी धंस रहा था। ऑक्सीजन कम हो रही थी, मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि बस अब नहीं हो पाएगा वापस चलते हैं, फिर भी चलते रहे, साहस जुटाते गए। हिम्मत भी टूट रही थी किन्तु ऐसे में एक दूसरे को हौसला देते हुए भारत माता की जय वंदे मातरम् के नारों के साथ कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे । 16 जून 2013 में जहां केदारनाथ आपदा आई थी उसी जगह 16 जुलाई 2022 को मयाली पास पार करते हुए 15 किलोमीटर की दूरी तय कर केदारनाथ से 5 किलोमीटर दूर वासुकी ताल पर हमारा बेस कैंप लगना था और हम सुबह 5:30 पर चल पड़े थे, मौसम बहुत खराब हो चुका था, बिजली का कड़कना बादल का गरजना, मेघ का बरसना, हवा का रुख कुछ बदल सा गया था, हम डर से रहे थे। सहमे से रहे थे पर हमारे शिक्षक के नाते अभिभावक के नाते चल रहे विनोद सर, महेंद्र सर, अनुप सर, विजय सर, प्रवीण सर ने हमारी हौसला को बढ़ाया और हम बढ़ चले। लगभग 12 घंटे चलने के बाद हम वासुकी ताल पहुंचे जहां पर फिर हमने अपना कैंप सेट किया,14 दिन की इस कठिन यात्रा के दौरान ऐसे अद्भुत दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य व अलग-अलग प्रकार के जीव-जंतु व चिड़िया भी देखने को मिले, शायद जो अपने जीवन काल में कहीं हमने नहीं देखे थे। उत्तराखण्ड में कई ऐसे शिखर हैं जिनको फतेह किया जाना अभी भी बाकी है, इन पहाड़ों को और प्राकृतिक सौंदर्य को अलविदा कहकर फिर कभी दोबारा आएंगे का संकल्प लेकर अपनी यात्रा पूरी हुई। अभाविप कार्यकर्ताओं ने यात्रा आयोजित करवाने के लिए उत्तराखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को धन्यवाद कहा। यात्रा में अभिषेक, जितेन्द्र, नवीन, कृष्णा, अजय, भूपेंद्र, अनिरुद्ध, प्रमोद, युवराज, कल्पना, सुनीता, गीतांजलि, रिंकी, दीपक, रोहन, देवेंद्र धीरज आदि कार्यकर्ता शामिल थे।

हूल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर अभाविप ने किया अमर बलिदानी सिदो-कान्हू के कृतित्व को याद

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 30 जून 2022 को हूल दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित अमर बलिदानी सिदो – कान्हू के कृतित्व को याद किया। हूल दिवस के मौके पर विद्यार्थी परिषद ने संगोष्ठी, मैराथन, क्वीज प्रतियोगिता का आयोजन किया। अभाविप झारखंड के दुमका नगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा हूल दिवस के अवसर पर हूल विद्रोह के नायक महान स्वतंत्रता सेनानी दुमका नगर के पोखरा चौक स्थित सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए अभाविप के विभाग संगठन मंत्री बब्बन बैठा ने कहा कि जब संथालों पर ब्रिटिश हुकूमत का शोषण, जुल्म, अन्याय, अत्याचार की अति हो गई, तब संथालों को विद्रोह के लिए विवश होना पड़ा। उस समय बरहेट प्रखंड के अंतर्गत भोगनाडीह गांव में चुन्नू मुर्मू की छह संतान, जिनमें चार लड़के और दो लड़कियां थीं। चार भाइयों और दो बहनों जिनका नाम सिदो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू था। इन सगे भाई-बहनों ने संथाल समाज के लोगों को जागृत किया और 30 जून 1855 को अंग्रेजो के खिलाफ विद्रोह की बिगुल फूंक दी। 1855 को ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध महान संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह को संताली भाषा में 'संताल हूल' कहते हैं। अपने देश व समाज के लोगों के लिए सिदो - कान्हू से प्रेरणा समाज के प्रत्येक युवा को लेने की आवश्यकता है।

अभाविप झारखंड प्रांत के प्रदेश जनजाति कार्य प्रमुख मनोज सोरेन ने कहा कि संथाल हूल के दौरान 1855 में 10,000 ग्राम वासियों के एक सभा में सिदो मुर्मू को राजा, कान्हू मुर्मू को महामंत्री, चांद मुर्मू को मंत्री तथा भैरव मुर्मू को सेनापति नियुक्त किया गया था। उसी समय चारों भाई एवं बहनों ने एक बड़ा ऐलान

कर दिया गया कि अब से ब्रिटिश शासकों को लगान नहीं देना है और न किसी जमींदार से कर्ज लेना है। फूलो – झानो ने भी अपने अलग महिलाओं की फौज खड़ी की थी। कहा जाता है कि फूलो-झानो उस समय 1000 ब्रिगेडियर के साथ चला करती थी तथा उनके साथ 10,000 के फोर्स रहते थे। इस विद्रोह में 200 गांव से लगभग 50,000 की संख्या में युद्ध में भाग लिए थे। प्रदेश सह छात्रा प्रमुख बिनीता कुमारी ने कहा कि संथाल परगना सहित समस्त झारखंड को समृद्ध और सशक्त बनाना ही ध्येय है। झारखंड का पर्यावरण सापेक्ष विकास, इसकी भाषा और लिपि, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए हम सबका साझा प्रतिबद्ध प्रयास ही इन वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। नगर मंत्री जयंत कुमार ने संथाल हूल के इतिहास के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल इस अवसर पर मुख्य रूप से विभाग संगठन मंत्री बबन बैठा, प्रदेश जनजाति प्रमुख मनोज सोरेन जिला सह संयोजक कृष्णा शील, प्रदेश सह छात्रा प्रमुख बिनीता कुमारी,नगर मंत्री जयंत कुमार ,नगर विद्यार्थी विस्तारक धनंजय कुमार सुमन कुमारी आदित्य राज सचिन कुमार उपेंद्र कुमार प्रह्लाद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लखीराम मंडल अभिषेक कुणाल आदि दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ABVP Telangana State office inaugurated by Mananiya Mohan Ji

Paramapujaniya Sarsanghachalak DR. Mohan Bhagwat ji called upon all of us to bring the country to a state of greatness without allowing arrogance to reach it. The inauguration ceremony of the newly constructed ABVP office "Spoorthi ChatraShakti Bhavan" in Hyderabad was held in a grand manner. RSS Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat ji was the chief guest at the event, ABVP All India Organizing Secretary Shri. Ashish Chauhan ji, ABVP All India General Secretary Kumari Nidhi Tripathi, were participated as guests.

Speaking on the occasion, Mohan ji Bhagwat congratulated all those who have endured many hardships and worked hard for a long time and achieved a task and under whose inspiration this office was built. He said that this office itself is a testimony to the confidence of the workers at our disposal that one day our idea is justified and it will have a victory. What is ABVP can be understood by looking at abvp's activity in Telangana. He recalled that all of you were happy and excited at this time but as mentioned in our sangh prayers, this was a kantakakirna path and we shed sweat and blood to speed up our work in adverse weather conditions.

He added that logicians who believe in truth and justice, who think that their own truth not greater than all others, have tried to suppress truth and justice by interest in their all energies, but the truth will never be hidden. He said that this office is the result of the penance of the martyred activists.

The name called spooorthy is very fit to the this bhavan . The ABVP's work here has a rich history and it is expected that an inspiration will emerge in our minds after seeing all this. From the very beginning, the ABVP's Telangana region has been at

the top, Telangana has stood up to show how to be the office has remained a trendsetter, standing up against adversaries on the one hand and avoiding the damage caused by on the other. He said both of them belonged to the abvp in Telangana and today's office is a replica of them.

As stated in sangh prayer, this is the path of the eyes, 30 years ago it was experienced for us and today's karyakarthas are asking where is the thorn in our path, that is, we should stop the inner sorrow of fighting during the time of patience and patience and resistance, and move forward for the cause of action for the activists, he said. Despite all this, we had to build self-control and confidence in ourselves so that we don't feel hostile," he said. Now the office has been set up and there are so many facilities. He said that it will go a long way in instilling faith and love in our society

"There was a time when everyone used to laugh at ABVP activists, used to make fun of Saraswathi prayers and congratulate those who stood first, but those who mocked us are now walking our path and they are doing the same things," he said. Those who did not care for us then are now recognizing us as the foremost.

When we get a level in society, we get arrogance... Like everyone else, we don't have to yearn for victory, it is not the goal of victory, it is only the way, many kings have won many battles, but we don't know them for more than 1,200,000 years and we want to take lord Rama as role model for ages , not just remembering Lord Ram, "We want to stand by his ideals and who took the path of the jungle for the rule of the father's word for the ages.

Julius Caesar was overwhelmed by arrogance, no matter how many victories he had achieved. But till now our Lord Rama is soaking in everyone's mouths by practicing dharma.

In some villages in Uttar Pradesh, the chickpea crop is not grown up to a few square kilometres. Because when Sita maata was walking to her house, she was bleeding from walking on these dried peanuts. So even today, peanuts are not grown for a few miles. He said that the Sita is still etched in our minds.

We need to be conscious of where we come from. There is no one in the world who has said good things about ourselves, there is no scolding, there is no propaganda for us from such a state of blame, where there is no government, where there is no experience, where we have risen with our own strength. It is essential to achieve big tasks with the strength of the workers and not with the facilities, he said, adding that the qualities of the activists have been developed and empowered by spirituality, mission and perseverance. We must never fall to scams, fame lies Mohan Bhagwat ji suggested to the students and student leader on the occasion that the unity of knowledge should be our only strength.

असली भारत तो गांवों में बसता है : नीखरा

दो साल बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सामाजिक अनुभूति के लिए फिर से गांव की ओर चल पड़े हैं। अभाविप ब्रज प्रांत के द्वारा सामाजिक संवेदना के प्रत्यक्ष अनुभूति हेतु 'चलो गांव की ओर' अभियान चलाया गया, इस अभियान के अंतर्गत शहरों में रहने वाले विद्यार्थी विभिन्न गांवों में गए और वहां के रहन – सहन, खान – पान, संस्कृति, परंपरा इत्यादि का प्रत्यक्ष दर्शन किए। दिन – रात लैपटॉप, आईपैड व मोबाईल के साथ गुजारने विद्यार्थियों के लिए यह अलग प्रकार का अनुभव था। बरगद और पीपल के छांव में बैठकर ग्रामीणों से मिलना, उनके जीवन चर्या के बारे में जानना एवं उसे संकलित रहना अनोखा अनुभव था। ग्रामीण क्षेत्रों में गए विद्यार्थियों के अनुसार यह उनके लिए बिल्कुल नया और अनोखा अनुभव था। उनलोगों ने कहा कि ग्रामीणों का आतिथ्य सत्कार और अपनापन पाकर अभिभूत हूं, हमलोगों को लग ही नहीं रहा था कि पहली बार उनके यहां गए हैं। इस दौरान हमलोगों ने आम के पेड़ से आम तोड़कर आम खाये, कटहल खाये, तालाब में नहाए, बिना इंटरनेट और इलेक्ट्रोनिक सामानों के कैसे दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। चिड़ियों का चहचहाना, गांव के बच्चों के साथ खेलना, रात में ग्रामीणों के साथ खुले आसमान के नीचे विश्राम करना काफी रोमांचित करता था लेकिन ग्रामीणों का जीवन काफी कष्ट भरा होता है। दिन भर खेतों में काम करना, घर आकर गाय एवं मवेशियों का देखभाल करना, उसके चारे उपलब्ध कराना आसान काम नहीं है। गांव में रहने वालों को अनेक कठिनाईयों से होकर गुजरना पड़ता है, प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। शहरों की तरह वहां पर सुविधाएं नहीं है, अनेकों कठिनाईयां हैं। विद्यार्थियों की मानें तो ग्रामीण भले ही धन से अमीर न हों लेकिन दिल के राजा होते हैं। अनेक परेशानियों में रहने के बावजूद वे आपस में मिलजुलकर रहते हैं, उनका आतिथ्य सत्कार देखकर लगता ही नहीं कि वे अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे

सामाजिक अनुभूति अभियान के बारे में बताते हुए क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज नीखरा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को ग्रामीणों के साथ रात्रि विश्राम कर उनके जीवन की कठिनाईयों को समझना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जीवन आज भी काफी कठिन है। कार्यकर्ताओं को उनके साथ रात्रि विश्राम करने पर कठिनाईयों की अनुभूति होगी एवं उनकी समस्याओं के बारे में जानकर हल करने का प्रयत्न भी करते हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक अनुभूति कार्यक्रम के बाद तरह तरह के अनुभव भी साझा करते हैं और फिर अनुभव होता है कि असली भारत तो गांव में बसता है

अभाविप ब्रज प्रांत के कार्यकर्ताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रज प्रांत के द्वारा ग्राम्य जीवन दर्शन यानी सामाजिक अनुभूति (चलो गांव ओर अभियान) का चार दिवसीय आयोजन 15 जून से 19 जून तक चलाया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को गांव – गांव जाकर ग्रामीण जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इस अभियान में ब्रज प्रांत के 15 जिलों से 687 कार्यकर्ताओं ने 114 टोलियां बनाकर 440 गांव में जाकर ग्रामीण जीवन के विभिन्न प्रकार के अनुभव लिए और ग्रामीण जीवन को आत्मसात किया। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अनुभूति कार्यक्रम चलाया जाता है परंतु कोरोना के कारण पिछले दो वर्षों से सामाजिक अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया था।

मंडी : अभाविप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 'अभ्युदय' का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिमाचल प्रदेश के सरदार पटेल मंडी विश्वविद्यालय, इकाई द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम अभ्युदय का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से मुख्य अतिथि राकेश जामवाल , विशिष्ट अतिथि शिल्पा कुमारी व कार्यक्रम अध्यक्ष दीपक पठानिया उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के विधिवत स्वागत से हुई। अभ्युदय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राकेश जामवाल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए अनेक आंदोलनों के परिश्रम से ही मंडी में विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई । उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद के लंबे समय के आंदोलन की जीत है कि यह दूसरा विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में बनने जा रहा है। विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो हमेशा समाज हित की बात हो या राष्ट्र हित की बात हो आगे रहता है। अभाविप अपने विविध आयाम के माध्यम से छात्र - छात्राओं की प्रतिभा को निखारने का कार्य कर रही है।

विशिष्ट अतिथि शिल्पा कुमारी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद ने कोरोना काल में भी पूरे समाज की सहायता की। जब पूरा देश कोरोना काल में घर के अंदर थे तो विद्यार्थी परिषद मैदान में सबकी सहायता करने के लिए आगे था। अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जब देश के सभी लोग अपने परिवार के मृत्यु पर भी बाहर नहीं आ रहे थे तो विद्यार्थी परिषद के मंडी के कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति का दाह संस्कार किया। कार्यक्रम अध्यक्ष दीपक पठनीया ने इस दौरान कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों, परिषद कार्यकर्ताओं सहित दर्शक व प्रतिभागियों का स्वागत किया।

अभ्युदय कार्यक्रम में दिखी हिमाचली संस्कृति की झलक

अभाविप द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम अभ्युदय में हिमाचली संस्कृति की झलक साथ दिखाई दी। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने हिमाचल की संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी। अपने विविध प्रस्तुतियों से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया, वहां उपस्थित दर्शक व अतिथि खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाए। अभ्युदय कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र व छात्राओं द्वारा 28 प्रस्तुति दी गई, जिसमें गणेश वंदना, पार्टियोटिक डांस, सिराजी नाटी, सुकेती नाटी, शिमला नाटी, किन्नौरी नाटी, कुल्लुवी नाटी, सोलो डांस, सिंगिंग आदि जैसी विभिन्न प्रतिस्पर्धा रही।

ABVP, DUSU meet V-C, call for centre to guide students

A joint delegation of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) and Delhi University Students Union (DUSU) met the university's Vice-Chancellor Yogesh Singh on 20th June and submitted a memorandum requesting him to set up an 'Incubation Centre' to guide students in various fields. They also urged the VC to launch the 'Earn while Learn' initiative, under which 10,000 students should be provided paid internships, ABVP said in a statement.

"The joint delegation of ABVP and DUSU held a meeting with the Vice-Chancellor of DU and submitted a memorandum requesting the authorities to set up 'Incubation Centre' for the students of DU to get guidance in various fields," the statement read.

"Students will be provided internship under this scheme according to their interest in many fields including sports, computers labs, laboratories," the statement added. ABVP and DUSU have also taken the initiative to set up 'Incubation Centres' in all the colleges of DU.

उदयपुर में जेहाद प्रणीत क्रूर हत्या के दोषियों पर हो शीघ्र कार्रवाई: अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राजस्थान के उदयपुर में एक दर्ज़ी की पांथिक कट्टरवादियों द्वारा कायरतापूर्ण की गयी जघन्य हत्या की तीव्र निंदा करती है। 10 दिन पूर्व में उक्त दर्ज़ी को मजहबी उन्मादियों द्वारा लगातार धमकियां मिल रहीं थीं, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया जिसकी परिणति अत्यंत दुखद घटना के रूप में हुई है।

उदयपुर में जेहादी मानसिकता के खूनी प्रदर्शन लिये गहलोत सरकार की लचर क़ानून व्यवस्था व तुष्टिकरण की राजनीति कारक है। अतः अभाविप गहलोत सरकार को अपना नींद से जाग कर अपना उत्तरदायित्व पहचान कर उचित कार्रवाई की मांग करती है।

सोशल मीडिया पर हत्या की ज़िम्मेदारी लेने वाले दो मुस्लिम युवकों द्वारा इस जघन्य कृत्य की वीडियो पोस्ट करने के कारण अनेक क्षेत्रों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उक्त घटना से राजस्थान सरकार की क़ानून व्यवस्था बनाए रखने की अक्षमता पुनः सामने आ गई है। इस घटना के बाद उपजी तनावपूर्ण स्थितियों में अभाविप देशवासियों से शांति की अपील करती है तथा हत्या के दोषियों पर शीघ्र कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करती है।

तीनों सेनाओं के नेतृत्व द्वारा स्वीकार्य अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना सामरिक दृष्टि से आवश्यक: अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, देश की तीनों सेनाओं के नेतृत्व द्वारा स्वीकार्य अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को सामरिक दृष्टि से आवश्यक, एवं कोरोना काल में आये व्यवधान को देखते हुए 2022 हेतु अधिकतम आयुसीमा 23 वर्ष तक बढ़ाने के निर्णय का स्वागत करती है।

'अग्निपथ' योजना की घोषणा के बाद जिस प्रकार से हिंसक तथा अराजक विरोध हुआ, वह बेहद निंदनीय है। युवाओं की चिंता का निवारण सरकार से बातचीत कर किया जा सकता है, परंतु हिंसा उत्थान का मार्ग नहीं हो सकता है। युवाओं की आशाओं को हिंसा के अवैध पथ पर मोड़ने के कुत्सित प्रयासों को रोकने के लिए विभिन्न स्तरों से स्वस्थ प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

देश की आंतरिक सुरक्षा के कूटनीतिक विषय में तीनो सेनाओं के नेतृत्व द्वारा वर्तमान समय की सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिए गए निर्णय पर विभिन्न राजनैतिक समूहों द्वारा बिना सोचे समझे की गई अनपेक्षित टिप्पणियों से अग्निपथ भर्ती योजना के देशहित में भावी उद्देश्यों की हानि हुई है,जो कि अत्यंत चिंताजनक तथा दुर्भाग्यपूर्ण है।

कोरोना काल में सैन्य भर्ती में आये व्यवधान के कारण लाखों युवा आयुसीमा पार कर गए है, जिसके निवारण हेतु परिषद ने जून 2021 में ही अधिकतम आयुसीमा में छूट की मांग की थी जिसे पूर्ण किया गया है।

अग्निवीरों को भविष्य में अर्द्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस तथा अन्य क्षेत्रों में विशेष आरक्षण दिए जाने की घोषणाओं का भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वागत करती है। सेना में प्रशिक्षित हुए अग्निवीर निश्चित ही अन्य क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण कार्य कर देश के विकास में सहभागी बनेंगे तथा इन क्षेत्रों में अपेक्षित सुधारों के वाहक होंगे।

यूपीए की एजेन्ट तीस्ता के षडयंत्र के अंत की कहानी

। आशीष कुमार 'अंशु' ।

यह बात अहमदाबाद में कौन नहीं जानता कि गुजरात संबंधी मामलों की विशेषज्ञ तीस्ता जावेद सीतलवार ने 2002 के दंगों की लाश का कफन बेचकर पैसा कमाया। वह गुलबर्गा सोसायटी में लाशों का एक संग्राहलय बनाना चाहती थी। इस संग्राहलय के नाम पर वह पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी को लेकर दुनिया भर के अलग-अलग देशों में गई। उसने साम्प्रदायिक दंगों को नरसंहार प्रचारित करके खूब सारा धन इकट्ठा किया। गुलबर्गा में लाशों का संग्रहालय तो नहीं बन पाया लेकिन इस नाम पर उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। अब इस बात को लंबा अर्सा गुजर गया, पैसे पता नहीं कहां गए? तीस्ता ने कहा था कि वह पैसे देकर गुलबर्गा खरीद लेगी लेकिन गुलबर्गा सोसायटी के लोग आज भी सड़क पर ठोकरे खा रहे हैं। उन्हें पैसा नहीं मिला। तीस्ता ने पीड़ितों का फोन तक उठाना बंद कर दिया।

जब 25 जून को तीस्ता की गिरफ्तारी की खबर मीडिया में आई तो ऐसा ही लगा कि अब उसे धोखाधड़ी की सजा मिलेगी जबकि गुजरात दंगा मामले में झूठी जानकारी देने के आरोप में गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़ को उसके घर से गिरफ्तार किया। मतलब धोखाधड़ी का मामला उस पर अलग से चलेगा। अहमदाबाद पुलिस अपराध शाखा में इंस्पेक्टर दर्शनसिंह बी बराड की शिकायत पर तीस्ता के अलावा पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार ने एसआईटी के सामने विधि व्यवस्था से जुड़े जिस बैठक का हवाला देकर अपना बयान दर्ज कराया था। अब जांच से यह बात सामने आई है कि ये दोनों उस बैठक में शामिल ही नहीं हुए थे। एफआईआर में इन पर यही आरोप लगे हैं कि आरोपियों ने जकिया जाफरी के माध्यम से न्यायालय में याचिकाएं लगाईं और एसआईटी और दूसरे आयोग को गलत जानकारियां देते रहे।

2002 गुजरात दंगों में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यूम में कहा कि जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी आरोपों को खारीज किया है। आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने यह आरोप राजनीति द्वारा प्रेरित है, सिद्ध किया है।

श्री शाह ने तीस्ता के नाम उल्लेख करते हुए कहा— मैंने बहुत जल्दबाजी में जजमेंट को पढ़ा है, लेकिन इसमें तीस्ता सीतलवाड़ का नाम बहुत स्पष्ट दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ने हर थाने में भाजपा के कार्यकर्ता को शामिल करने वाली ऐप्लिकेशन दी थी। मीडिया का दबाव इतना था कि ऐसी ऐप्लिकेशन को सच मान लिया गया। जनता ने कभी इन आरोपों को स्वीकारा नहीं। लेकिन मीडिया, एनजीओ और हमारी विरोधी पॉलिटिकल पार्टियों ने भाजपा के खिलाफ गलत आरोपों को चलाया।

वर्ष 2002 के फरवरी महीने में गुजरात में साम्प्रदायिक दंगे हुए, उन दिनों तीस्ता मुम्बई में रहती थी। तीस्ता को पीड़ितों की मदद के लिए अहमदाबाद आने का न्योता रईस खान पठान नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने दिया था। रईस के बुलाने पर ही तीस्ता मुम्बई से कथित तौर पर पीड़ितों की मदद के लिए गुजरात आई थीं। रईस मुम्बई के साम्प्रदायिक दंगों के समय तीस्ता के साथ काम कर चुके थे। वे तीस्ता को गुजरात दंगों के पीड़ितों तक लेकर गए। तीस्ता ने पीड़ितों का वीडियो बनाकर वेवसाइट पर डाला।

उनकी एक पत्रिका थी, 'कम्युनलिज्म कॉम्बैट', उसमें उन्होंने तमाम पीड़ितों और फरियादियों की तस्वीर और बयान को इंगलिश और गुजराती में प्रकाशित किया था।

गुजरात आने से पहले तीस्ता एक अंग्रेजी अखबार में काम कर चुकी थी। उसने अपने संबंधों का इस्तेमाल करके मीडिया में अपनी ब्रांडिंग प्रारंभ कर दी। तीस्ता ने गुलबर्गा, नरोडा पाटिया, नरोडा गांव, ओड, सरदारपुर में पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई जमीन पर कम, मीडिया और फंडिंग एजेन्सी के सामने अधिक लड़ी है।

इस पूरे मामले पर जब रईस खान पठान से बात हुई थी, उन्होंने बताया - होता यह था कि तीस्ता जो एफिडेविट तैयार करती थी, पीड़ितों से नोटरी कराके अपने पास ही रखती थी। 2002-12 तक बिना किसी रोक टोक के वह यह सब करती रही। मतलब पीड़ितों को पता ही नहीं होता था कि तीस्ता उनके नाम पर क्या बयान लिख रही है।

2007 में दो ढाई लाख रुपए में अहमदाबाद में रहने लायक घर मिल जाता था। 24 दिसम्बर 2007 गुलबर्गा सोसायटी के एक पीड़ित मोहम्मद शरीफ नसरूद्दीन शेख के पास गुलबर्गा सोसायटी के लिए 01 करोड़ 86 लाख का आफर लेकर एक खरीददार आया था। इस सोसायटी में कुल सोलह घर थे। इस मामले में मोहम्मद शरीफ, रईस खान की राय जानना चाहते थे। रईस ने कहा- तीस्ता से बात करनी होगी।

मोहम्मद शरीफ के प्रस्ताव के संबंध में जब रईस ने तीस्ता को बताया, वह पर नाराज हो गईं। उसका कहना था- तुमने यह होने कैसे दिया? उनके पास ग्राहक आए कैसे? सोसायटी बेचने का ख्याल भी उनके दिमाग में कैसे आया? फिर तीस्ता ने रईस को अहमदाबाद उच्च न्यायालय में वकील सुहेल तीरमिजी के पास गुलबर्गा सोसायटी के लोगों को लेकर आने को कहा। 25 दिसम्बर 2007 को तमाम लोग वकील के यहां इकट्ठे हुए। तीस्ता ने वहां कहा कि मैं नहीं चाहती कि यह सोसायटी बिके। दो महीने में आपसे यह सोसायटी पैसे देकर मैं खुद खरीद लूंगी। तीस्ता ने अपना यह वादा पूरा नहीं किया।

फिर आया साल 2012, जब गुलबर्गा सोसायटी के पीड़ितो ने पुलिस में जाकर तीस्ता के खिलाफ शिकायत लिखाई। पीडितों का कहना था कि तीस्ता गुलबर्गा सोसायटी के पीड़ितों के नाम का इस्तेमाल करती है और उनके नाम पर 28 फरवरी को प्रत्येक साल सोसायटी के अंदर कार्यक्रम करती है। बड़े-बड़े लोगों और मीडिया को बुलाती है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करती है और उस डॉक्यूमेन्ट्री के ऊपर पैसे लाती है लेकिन उन पैसों से सोसायटी के लोगों की कोई मदद नहीं हो रही। गुलबर्गा के लोगों ने पुलिस से निवेदन किया कि तीस्ता का प्रवेश सोसायटी में प्रतिबंधित किया जाए। तीस्ता ने गुजरात दंगों के दौरान सबरंग ट्रस्ट' और 'सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस' नाम के दो एनजीओ में पैसे मंगाए। इसके अलावा तीस्ता ने 'सबरंग कम्युनिकेशन' नाम से एक फर्म भी बनाया हुआ है।

प्रकारान्तर में तीस्ता ने रईस खान को अपनी एनजीओ से अलग कर दिया। जब रईस ने तीस्ता को एनजीओ से अलग किए जाने की वजह जानने के लिए फोन किया तो बकौल रईस खान उन्होंने धमकाते हुए कहा — ''आज के बाद आप सीजेपी (Citizens for Justice and Peace) में नहीं हैं। आगे से मुझे फोन ना कीजिए। बाकि केन्द्र की सरकार से मेरी नजदीकी है। इस बात का अंदाजा तुम्हे होगा। मैं तुम्हारी पूरी जिन्दगी खत्म कर दूंगी और पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां चले गए?''

कांग्रेस की सरकार ने गुजरात दंगों में उनकी सक्रियता को देखते हुए 2002 में ही राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया और 2007 में फिर उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा तीस्ता नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की भी सदस्य थीं, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थीं। आरोप तो यह भी लगते रहे हैं कि कांग्रेस ने तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को जो 1.4 करोड़ रुपये दिए थे। इसका उपयोग मोदी के खिलाफ अभियान चलाने और भारत को बदनाम करने के लिए किया गया।

आज कांग्रेस, तीस्ता और 'तहलका के स्टिंग' का सच समाज के सामने है। तहलका ने गुजरात 2002 पर किए गए अपने स्टिंग को संदर्भ से काटकर

कांग्रेस के पैसे पर तीस्ता करे षडयंत्र

गुजरात 2002 को लेकर नरेन्द्र मोदी का इस देश में जैसा मीडिया ट्रायल चला। भारत के इतिहास में शायद ही किसी मामले का ऐसा मीडिया ट्रायल हुआ हो। न्यायालय में चल रहे मामले का निर्णय आने से पहले राजदीप, बरखा , करण थापर जैसे पत्रकार, सोनिया गांधी जैसी नेता और तीस्ता सीतलवाड़, शबनम हाशमी जैसे एनजीओ वालों ने पूरे मामले के लिए मोदी को दोषी साबित कर दिया था। न्यायालय के निर्णय से पहले इनका निर्णय आ गया था। हाल में एक साक्षात्कार में गृह मंत्री अमित शाह ने राजनेता, मीडिया और एनजीओ की इस तीकड़ी का उल्लेख किया था। 2002 के संदर्भ में इनका आपसी परस्पर सहयोग देखते ही बनता था। यही साल था जब भारतीय राजनीति में यूपीए की नैरेटिव का तीसरा फ्रंट मीडिया और एनजीओ ने संभाला। 2004 में यूपीए की सरकार बनी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और सोनिया गांधी एनएसी की अध्यक्ष। आधिकारिक तौर पर तीस्ता सीतलवाड़ सोनिया गांधी के एनएसी में अपनी सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता की वजह से जुड़ी लेकिन उन्हें नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सतत प्रोपगेन्डा करने का ईनाम मिला था। यूपीए की सरकार में देश के सबसे अधिक शक्तिशाली लोगों में तीस्ता का नाम शामिल हो गया था। जो काम कांग्रेस सरकार में अच्छे अच्छों के वश की बात नहीं थी। वह तीस्ता करा ले जाती थी। इस बात के अनेक प्रमाण है कि कांग्रेस ने कभी तीस्ता को अकेले नहीं पड़ने दिया। उसकी दोनों हाथों से मदद की। बदले में साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अपनी लड़ाई के नाम पर वह खूब सारा पैसा इकट्ठा कर रही थी और भाजपा और नरेन्द्र मोदी के खिलाफ षडयंत्रों में उसका एक हिस्सा खर्च कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद तीस्ता का असली चेहरा पूरे देश के सामने चाहे बेनकाब हुआ हो लेकिन उसका सच बहुत सारे लोग पहले से ही जानते थे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुनकर वे आश्चर्यचकित नहीं हुए क्योंकि उसमें कुछ अनपेक्षित नहीं था। जो तीस्ता का सच था, वहीं सब सामने आया।

परोसा। आगे—पीछे की सारी फूटेज देखने के बाद। सभी आरोप बेबुनियाद साबित हुए। अब बरखा दत्त, राजदीप और करण थापर जैसे लोग देश से माफी मांगेगे? उस झूठ के लिए जिसे उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन पर बार—बार दुहराया।

लगातार और बार बार गुजरात 2002 का मीडिया ट्रायल किया गया। सर्वोच्च न्यायालय से आए निर्णय के बाद यह अच्छा नहीं होगा कि एनडीटीवी हमेशा के लिए अपनी स्क्रीन काली कर ले।

कांग्रेस का तीस्ता प्रेम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जब केन्द्रिय मंत्री थे तो तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को खूब सारा धन मुहैया करा रहे थे और जब वे मंत्री नहीं रहे तो तीस्ता की वकील की भूमिका में आ गए। एक बार उसके लिए आधी रात को न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तीस्ता को जमानत दिलवाई।

कांग्रेस की सरकार से चंदे का मोदी के खिलाफ इस्तेमाल

- अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) राजदीप सिंह ज़ाला के अनुसार, उन्हें एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीतलवाड़ और उनके एनजीओ के ट्रस्टी ने 2010 और 2013 के बीच केंद्रीय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 1.4 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने में धोखाधड़ी की। उसके आधार पर पुलिस ने सीतलवाड़ और उनके एनजीओ के ख़िलाफ़ एक प्राथमिकी दर्ज की.'

- 2010 से लेकर 2013 तक देश में यूपीए की सरकार थी।2009—12 तक देश मानव संसाध विकास मंत्री कपिल सिब्बल थे। न्यायालय में चल रही कार्रवाई में कपिल सिब्बल अब तीस्ता के वकील की भूमिका में है।
- इस फंड का एक बड़ा हिस्सा सबरंग ट्रस्ट से सिटिजेंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) और तीस्ता के एक दूसरे एनजीओ को चंदे के रूप में दिया गया, जिसे गुजरात के ऑफिस कर्मचारियों की तनख़्वाह, गुजरात दंगा पीड़ितों से मिलने में, वकीलों की फीस और गुजरात सरकार के ख़िलाफ़ विभिन्न अभियान चलाने में ख़र्च किया गया.'
- तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति के दो एनजीओ पर करोड़ो रुपए के गबन का आरोप है। यह सब तत्कालीन यूपीए सरकार और सोनिया गांधी के सहयोग के बिना संभव नहीं था।

अहमद पटेल के संपर्क में थी तीस्ता

तीस्ता सीतलवाड़ के पूर्व सहयोगी रईस खान के अनुसार, ''तीस्ता कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के संपर्क में थीं। वह पटेल से मोदी विरोधी अभियान के मुद्दे पर चर्चा करती थीं। वह कांग्रेस के अन्य नेताओं के भी संपर्क में थीं। उस समय तीस्ता और कांग्रेस का एजेंडा एक था, मोदी को निशाना बनाना।

साम्प्रदायिकता बहाना, भाजपा निशाना

- 2007 के चुनाव में तीस्ता ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रचार भी किया था। प्रश्न यह है कि जब तीस्ता खुद को एनजीओ कहती हैं। वह गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए कथित तौर पर गुजरात में सक्रिय हुईं। ऐसे में उनका चुनाव प्रचार के अभियान में शामिल होना। किसी एक पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना। दूसरी पार्टी को लाभ पहुंचाना। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ही स्पष्ट करता है।
- गुजरात में जब दो राजनीतिक पार्टियां हैं। तीस्ता भाजपा के खिलाफ प्रचार करने मैदान में उतरी थी तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि वह कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रही थी।

तीस्ता की साथी कांग्रेस वाली शबनम

मोदी के खिलाफ तीस्ता के अभियान में शबनम हाशमी महत्वपूर्ण भूमिका में थीं। शबनम जब सामाजिक कार्यकर्ता के वेश में तीस्ता साथ मोदी विरोधी अभियान में शामिल थी, उस समय वह गुजरात कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक तौर पर हिस्सा थीं।

दिग्विजय सिंह से मिली मदद

यह बात सिर्फ अनुमान के आधार पर नहीं कही जा रही बल्कि गुजरात दंगों के बाद तीस्ता सीतलवाड़ की सक्रियता और कांग्रेस परिवार से उसे मिल रही मदद से बार—बार कांग्रेस और तीस्ता का रिश्ता स्पष्ट हुआ है। मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह सरकार ने जब बजट की कटौती के नाम पर पत्र पत्रिकाओं की बजट में कमी की। उस दौरान भी तीस्ता की गुमनाम मासिक पत्रिका Communalism Combat पर प्रदेश सरकार का प्रेम निरंतर बना रहा।

सोनिया गांधी की सलाकार परिषद में भी रही शामिल

इन तमाम बिन्दुओं के अलावा यह सर्वविदित है कि तीस्ता यूपीए सरकार में गठित एनएसी (National Advisory Council) में शामिल थी। जिसमें गांधी परिवार के खास—खास लोगों को ही जगह मिली थी।

कांग्रेस से इतना प्रगाढ़ संबंध होने के बावजूद तीस्ता यदि कहें कि कांग्रेस से उनका कोई संबंध नहीं या कांग्रेस कहे कि तीस्ता से उनका कोई संबंध नहीं तो यह बात हास्यास्पद ही मानी जाएगी।

परिषद गतिविधियां

सिरोही (जोधपुर प्रांत) : राष्ट्रीय कला मंच द्वारा आयोजित 'इंद्रधनुष' कार्यक्रम में प्रस्तुति देते प्रतिभागी

मंडी (हि.प्र.) : अभाविप द्वारा आयोजित 'अभ्युदय' सांस्कृतिक कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य करते प्रतिभागी

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 JULY, 2022
DATE OF PUBLISHING: 8 JULY, 2022

POSTAL REGD. NO.: DL(C)-11/1409/2020-2022
POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI

महान स्वतंत्रता सेनानी उ तिरोत सिंह
बलिदान दिवस 17 जुलाई 1835

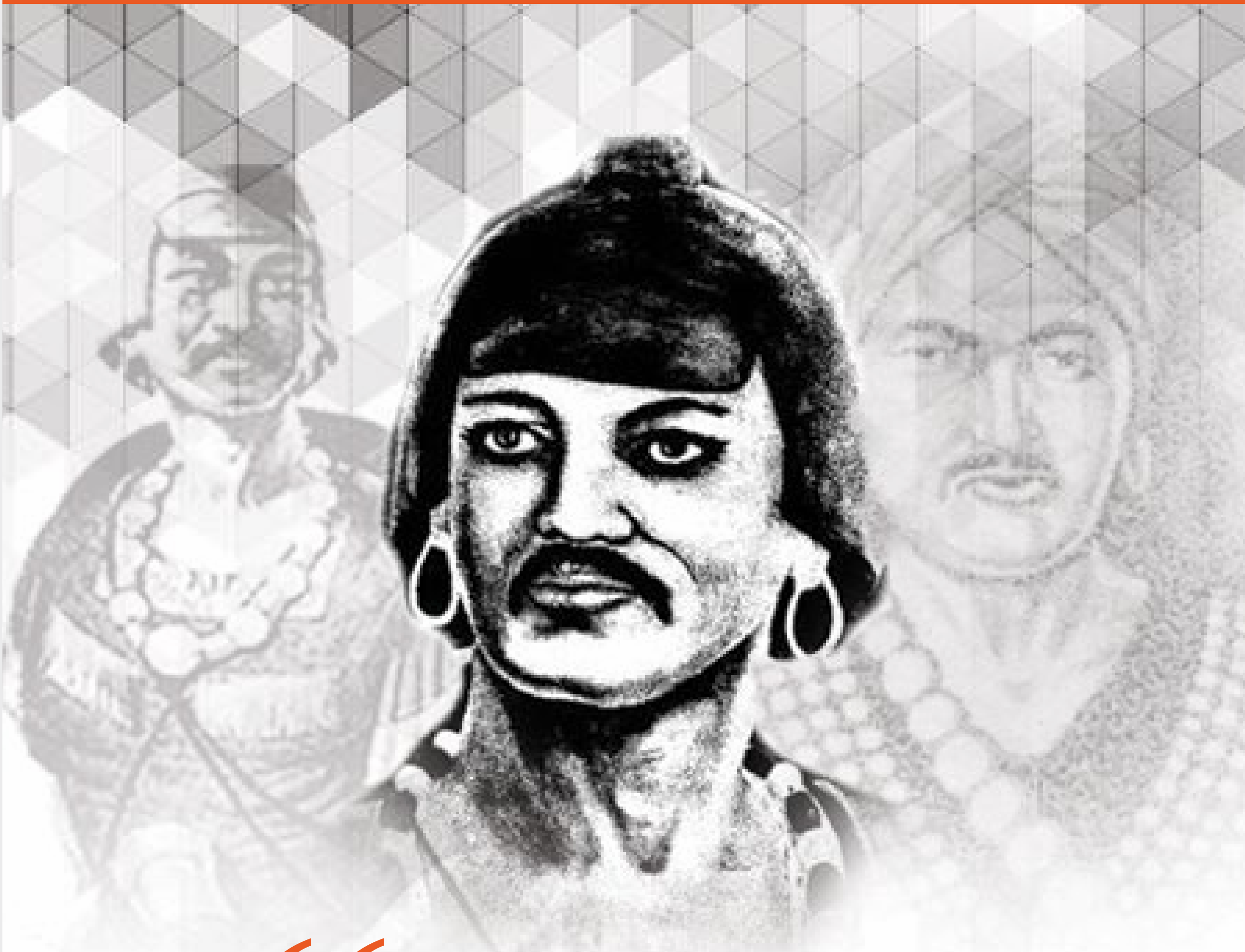

“Remembering
supreme sacrifice of brave Khasi chief

U Tirot Singh

on his 187th death anniversary”